भारत ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु ऊर्जा चालित एक पनडुब्बी से लगभग 3,500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इन मिसाइलों से भारत की सामरिक क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।..

जनहितैषी

हिन्दी दैनिक

जनहितैषी अब janhitaishinews.com पर भी

R.N.I. No. 64278/96 वर्ष:29 अंक:204 दिनांक:29-11-2024 शुक्रवार मूल्य:1 रूपया 50 पैसा पृष्ठ:4 वडोदरा M

महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद तेज, अमित शाह के आवास पर बैठक शुरू; एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजित पवार मौजूद

वक्फ संशोधन बिल पर घमासान, बढ़ा जेपीसी का कार्यकाल

शीतकालीन सत्र में नहीं आएगा वक्फ बिल

नई दिल्ली(ईएमएस)। संसद के चालू शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते के अंतिम दिन संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को वक्फ बिल पर अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करनी थी। यह इस सत्र के एजेंडे में भी शामिल था। जेपीसी में शामिल विपक्षी दलों के सांसद कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर रहे थे लेकिन इस समिति की अगुवाई कर रहे भाजपा के सांसद जगदंबिका पाल का दावा था कि हमारी रिपोर्ट तैयार है। जेपीसी की रिपोर्ट सदन में पेश किए जाने से एक दिन पहले इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। जेपीसी के प्रमुख जगदंबिका पाल ने और समय की मांग करते हुए कार्यकाल बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जिसे पारित कर दिया गया है। जेपीसी अब चालू शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते के अंतिम दिन यानी 29 नवंबर की जगह बजट सत्र 2025 के अंतिम दिन अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करेगी।

विपक्षी दलों के हंगामे के बीच वक्फ बिल पर बनी जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के व्यवहार की निंदा की। किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे विपक्ष के नेता और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सदस्यों ने जो बिल आने वाले हैं, उनके लिए समय निर्धारित किया था। हमने यह आग्रह भी किया था कि जो बिल आने हैं उन पर चर्चा के लिए उचित समय दिया जाए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जो अलग-अलग मुद्दे आने वाले हैं, उन पर भी चर्चा के लिए अलग रूल बने हुए हैं। यहां कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने हंगामा करके अपने ही बनाए रूल को तोड़ने का जो काम किया है, इसकी निंदा करता हूं। ये सही नहीं है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने आगे कहा कि सभी दलों ने आग्रह किया कि जिन मुद्दों की हियरिंग जेपीसी ने किया है, उसके लिए समय चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम इस पर भी राजी हो गए। यह प्रस्ताव जब आया, खुद कांग्रेस पार्टी हंगामा कर रही है जो उचित नहीं है।

बांग्लादेश में इस्कॉन पर बैन लगाने से कोर्ट का इनकार

-यूनुस सरकार ने कहा- हमने संगठन के खिलाफ जरूरी कदम उठाए

ढाका(ईएमएस)। बांग्लादेश में इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग को ढाका कोर्ट ने खारिज कर दिया है। गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा कि इस्कॉन की गतिविधियों के खिलाफ हमने जरूरी कदम उठाए हैं। यह मुद्दा सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने कहा कि इस्कॉन के मामले में अभी तक 3 केस दर्ज किए गए हैं और 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सेना को देश में किसी भी तरह की अशांति को रोकने के लिए तैनात किया गया है।

सुनवाई के दौरान याचिका दायर करने वाले वकील ने कहा कि इस्कॉन पर बैन लगाने का यही सही समय है। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह सरकार तय करेगी। दरअसल, इस्कॉन मंदिर के प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास प्रभु की राजद्रोह में गिरफ्तारी के बाद वहां संगठन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। दास को जेल भेजे जाने के बाद बांग्लादेश में कई जगहों पर हिंसा हुई है। साथ ही इससे बांग्लादेश और भारत सरकार के रिश्तों में भी दरार आई है।

चटगांव में 26 नवंबर को इस्कॉन प्रमुख की जमानत नामंजूर हो गई थी, जिसके बाद हुई हिंसा में एक वकील सैफुल इस्लाम की जान चली गई थी। इसके बाद 27 नवंबर को बांग्लादेश हाईकोर्ट में इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। याचिका दायर करने वाले वकील ने कोर्ट में कहा था कि सैफुल की मौत के पीछे इस्कॉन के लोग शामिल हैं। ऐसे में इस संस्था को बैन किया जाए। इस अर्जी में चटगांव में इमरजेंसी घोषित करने की भी मांग की गई थी। इस याचिका पर बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल मुहम्मद असदुज्जमां ने इस्कॉन को एक धार्मिक कट्टरपंथी संगठन बताया था।

इंडिया गठबंधन के नेताओं की मौजदूगी में हेमंत सोरेन बने झारखंड के चौथी बार मुख्यमंत्री

मंत्रिमंडल पर संशय, इसलिए अकेले ही ली पद व गोपनीयता की शपथ

रांची (ईएमएस)। झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन को बड़ी जीत मिली थी। चुनाव नतीजे आने के पांच दिन बाद झारखंड को अब नई सरकार मिल गई है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने हेमंत सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया है। हेमंत सोरेन ने रांची में आयोजित भव्य कार्यक्रम में झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली।

हेमंत चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। सीएम के साथ छह से आठ मंत्रियों के भी शपथ लेने की चर्चा थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सीएम के साथ किसी मंत्री ने शपथ नहीं ली। हेमंत के शपथ ग्रहण में उनके पिता और तीन बार के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन भी मौजूद रहे।

हेमंत सरकार के गठन के मौके पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने भी शामिल होकर शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद रहे।

गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट के साथ गठबंधन के साथ मैदान में उतरी थी। जेएमएम की अगुवाई वाले गठबंधन को 56 सीटों पर जीत मिली थी। झारखंड विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 81 है और बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़ा 41 विधायकों का है। इंडिया ब्लॉक का नंबर बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े से भी 15 ज्यादा है।

जेएमएम को ही 34 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को 16, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) को चार और लेफ्ट को दो सीटो सीटों पर जीत मिली थी। चुनाव नतीजों के बाद अगले ही दिन सोरेन ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया था। मुख्यमंत्री पद को लेकर किसी भी तरह का कोई सस्पेंस नहीं था लेकिन मंत्रिमंडल की तस्वीर पर गठबंधन के घटक दलों में सहमति अभी नहीं बन सकी है। इसकारण सोरेन ने अकेले ही पद एवं गोपनीयता की शपथ ली।

के-4 बैलिस्टिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग

नई दिल्ली(ईएमएस)। इंडियन नेवी ने के-4 बैलिस्टिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग की। यह टेस्टिंग न्यूक्लियर सबमरीन अरिघात से की गई थी। अरिघात को 2017 में लॉन्च किया गया था। इसका अपग्रेड वर्जन जल्द ही कमीशन किया जाएगा। अरिघात आईएनएस अरिहंत का अपग्रेडेड वर्जन है। इसे विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया था। अरिहंत की तुलना में अरिघात 3500 किलोमीटर की रेंज वाली के-4 मिसाइलों से लैस होगी। इस सबमरीन का वजन 6 हजार टन (60 हजार क्विंटल) है।

संसद में जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना मेरी प्राथमिकता रहेगी : प्रियंका गांधी वाड्रा

नई दिल्ली (ईएमएस)। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि उनके लिए संविधान सबसे ऊपर है और संसद में जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। श्रीमती वाड्रा ने लोकसभा की सदस्यता की शपथ के बाद कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ वे संविधान को मजबूती प्रदान करने की लड़ाई लड़ती रहेंगी और जनता के मुद्दे संसद में उठाना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा, ''जनता के जरूरी मुद्दों को उठाना, देश और पार्टी के लिए काम करना ही मेरी प्राथमिकता रहेगी। हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। हम संविधान के उसूलों के लिए लड़ते हैं और आगे भी लड़ते रहने वाले है।

इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि श्रीमती वाड्रा के संसद में आने से पार्टी को नई ऊर्जा मिली है। खरगे ने कहा, ''हमें संसद में एक नई ऊर्जा और शक्ति मिली है। प्रियंका जी चीजों को अच्छी तरह से समझती हैं और जनता के मुद्दों को उठाती हैं। उनके संसद में आने से हमारी पार्टी, जनता और खासकर देश की महिलाओं को फायदा होगा।''

चिन्मय प्रभु से नाता तोड़ते हुए इस्कॉन ने कहा- उनके लिए इस्कॉन जिम्मेदार नहीं

ढाका (ईएमएस)। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद इस्कॉन ने उनसे नाता तोड़ लिया है। इस्कॉन बांग्लादेश के महासचिव चारु चंद्र दास ने कहा कि इस्कॉन चिन्मय कृष्ण दास के किसी भी बयान या गतिविधि की जिम्मेदारी नहीं लेता। उन्होंने ढाका में एक प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि चिन्मय प्रभु को निष्कासित कर दिया गया है। यह बयान उस समय आया जब बांग्लादेश में हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद विवाद गहरा गया है। दास को सोमवार को चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद इस्कॉन समर्थकों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में विरोध फैल गया था जिसके बाद इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई।

इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की याचिका खारिज

को प्रतिबंधित करने के लिए बांग्लादेश हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस्कॉन को प्रतिबंधित करने से इनकार कर दिया। अदालत ने यह कहते हुए इस्कॉन की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का मामला खारिज कर दिया कि बिना ठोस सबूत के इस पर स्वत: संज्ञान नहीं लिया जा सकता। हाई कोर्ट के फैसले के बाद इस्कॉन के कोलकाता शाखा के उपाध्यक्ष राधारमन दास ने इसे न्याय की जीत बताया। उन्होंने कहा, हम पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। यह लाखों भक्तों के लिए राहत की बात है।

भारत और रूस के बीच एक महत्वपूर्ण सैन्य बैठक मॉस्को में संपन्न

मास्को,(ईएमएस)। भारत और रूस के बीच एक महत्वपूर्ण सैन्य बैठक रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित की गई। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारत और रूस के बीच सैन्य सहयोग पर कार्य समूह की चौथी बैठक थी। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह कार्य समूह, भारत-रूस रक्षा सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। साथ ही दोनों देशों को उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने व सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए मंच प्रदान करता है। सैन्य और सैन्य-तकनीकी सहयोग से संबंधित भारत-रूस अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत यह सैन्य बैठक मॉस्को में संपन्न हुई।

यह बैठक दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी को निरंतरता देने में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुई है। बैठक की सह-अध्यक्षता भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जेपी मैथ्यू ने की। वहीं रूस की ओर से सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ (मुख्य परिचालन निदेशालय) के उप-प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल डाइलेव्स्की इगोर निकोलाविच ने बैठक की सह अध्यक्षता की। दोनों सेनाओं के बीच परिचालन तालमेल को और मजबूत करने के लिए संयुक्त अभ्यासों का विस्तार करने पर भी सहमति व्यक्त की गई।

दोनों देशों ने सतह, हवाई और समुद्री क्षेत्रों में कई संयुक्त अभ्यास किए हैं। 'इंद्र', 'एविया इंद्र' और 'इंद्र नेवी' जैसे अभ्यासों ने सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, संयुक्त रणनीति अभ्यास और प्रक्रियाओं में सुधार लाने और आपसी समझ को गहरा करने के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम किया है।

जज देश में आग लगवाना चाहते हैं

रामगोपाल यादव ने लांघी सीमा, जजों पर की अपमानजनक टिप्पणी

नई दिल्ली (ईएमएस)। अजमेर शरीफ दरगाह विवाद पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने अपनी सीमा लांघते हुए जजों पर अपमानजनक टिप्पणी की है। रामगोपाल यादव ने कहा कि छोटे छोटे जज देश में आग लगवाना चाहते हैं। हाल में उन्होंने रिटायर हो चुके चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर भी विवादित टिप्पणी की थी और बाद में यूटर्न ले लिया था। बता दें कि अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करते हुए दायर याचिका कोर्ट में मंजूर होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले को लेकर राजनीति तेज हो गई है। राम गोपाल यादव ने कहा, ऐसा है मैंने पहले भी कहा था, इस तरह के छोटे-छोटे जज बैठे हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है इसका। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चादर भिजवाते हैं। देश दुनिया से लोग वहां आते हैं। उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता है। सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं, देश में आग लग जाए इससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। सत्ता में बने रहें बस। राजस्थान के अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करते हुए एक वाद स्थानीय अदालत में दायर किया गया है। अदालत ने बुधवार को याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए तीन पक्षकारों को नोटिस जारी किया। वादी विष्णु गुप्ता के वकील योगेश सिरोजा ने अजमेर में बताया कि वाद पर दीवानी मामलों के न्यायाधीश मनमोहन चंदेल की अदालत में सुनवाई हुई।

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर भारत के राज्यों में न्यूनतम तापमान में गिरावट का अनुमान जताया

नई दिल्ली (ईएमएस) । भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर भारत के राज्यों में न्यूनतम तापमान में गिरावट का अनुमान जताया है, वहीं पर कई राज्यों में सुबह के वक्त घना कोहरा छा सकता है। हालांकि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में अगले कुछ दिनों में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। साथ ही पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बारिश की संभावना है।

घाटी के अधिकतर हिस्सों में रात का तापमान शून्य से नीचे जाने के कारण श्रीनगर शहर और कश्मीर के अन्य इलाकों में इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे 2।1 डिग्री सेल्सियस रहा जो पिछली रात शून्य से नीचे 0।6 डिग्री सेल्सियस था। हालांकि, रात का तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस कम रहा। दक्षिण कश्मीर में काजीगुंड में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे तीन डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो इस मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान रहा। पहलगाम पर्यटक रिजॉर्ट में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे पांच डिग्री सेल्सियस रहा जो घाटी का सबसे ठंडा मौसम केंद्र है। रिजॉर्ट में यह मौसम की सबसे ठंडी रात भी रही।

राजस्थान के सीकर में बीती रात न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार बीती रात न्यूनतम तापमान सीकर के फतेहपुर में 6.6 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 8.2 डिग्री, सिरोही में 8.4 डिग्री, संगरिया में 8.7 डिग्री और अलवर में 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा सीकर, करौली, श्रीगंगानगर और जालोर में यह 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा।

राज्य के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान अब भी 30 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है। बीते चौबीस घंटे की अवधि के दौरान यह सीमावर्ती बाड़मेर में यह सबसे अधिक 32.8 डिग्री सेल्सियस रहा, इसके अलावा फलोदी में यह 31।6 डिग्री तथा जोधपुर में 31.2 डिग्री रहा।

दिल्ली में बृहस्पतिवार को सुबह प्रदूषण का स्तर थोड़ा बढ़ गया और वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, सुबह नौ बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 313 दर्ज किया गया, जबकि बुधवार को सुबह नौ बजे यह 301 था। राष्ट्रीय राजधानी में धुंध की मोटी परत छाई रही।

शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा, 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक, 101 से 200 के बीच 'मध्यम, 201 से 300 के बीच 'खराब, 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब तथा 401 से 500 के बीच एक्यूआई को 'गंभीर श्रेणी में माना जाता है।

देश में पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने 9.12 लाख करोड़ रुपये निवेश करेगी मोदी सरकार

नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश में पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 2031-32 तक 9.12 लाख करोड़ रुपये निवेश की योजना बना रही है। यह जानकारी केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक ने राज्यसभा में इसकी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, राष्ट्रीय विद्युत योजना (ट्रांसमिशन) के अनुसार, 2022-23 से 2031-32 तक के 10 साल की अवधि में 1.91 लाख किलोमीटर (किमी) ट्रांसमिशन लाइनें और 1274 गीगा वोल्ट एम्पीयर (जीवीए) ट्रांसफॉरमेशन क्षमता (220 केवी और ऊपर के वोल्टेज स्तर पर) जोड़ी जाएगी। इसके अलावा 33.25 गीगावॉट हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (एचवीडीसी) बाय-पोल लिंक की भी योजना तैयार की जा रही है।

इसके अलावा अंतर-क्षेत्रीय ट्रांसमिशन क्षमता को वर्तमान स्तर 119 गीगावॉट से बढ़ाकर 2026-27 तक 143 गीगावॉट और 2031-32 तक 168 गीगावॉट तक बढ़ाने की योजना है। इस प्लान में ट्रांसमिशन के नए टेक्नोलॉजी विकल्पों, क्रॉस-बॉर्डर इंटरकनेक्शन और ट्रांसमिशन में निजी सेक्टर की भागीदारी पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय विद्युत योजना (ट्रांसमिशन) में नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के साथ मौजूदा और योजनाबद्ध इंटरकनेक्शन को भी कवर किया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने उच्च सदन को बताया कि वर्तमान में देश में कुल 13,997.5 मेगावाट की 28 जलविद्युत परियोजनाएं (एचईपी) और 6,050 मेगावाट की पांच पंप स्टोरेज परियोजनाएं (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं। कुल 19,460 मेगावाट की 28 एचईपी और 4,100 मेगावाट की चार पीएसपी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा एप्रूव किया गया है। उन्होंने कहा कि कुल 8,036 मेगावाट की 11 एचईपी सर्वेक्षण और जांच (एस एंड आई) के अधीन हैं। इसके अलावा बताया कि मौजूदा समय में 29,200 मेगावाट कोयला आधारित क्षमता निर्माणाधीन है, 18,400 मेगावाट क्षमता आवंटित की जा चुकी है और 47,240 मेगावाट संभावित क्षमता विचाराधीन है। मंत्री ने आगे बताया कि 31 अक्टूबर तक कुल 1,27,050 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता कार्यान्वयन के अधीन है, जबकि 89,690 मेगावाट बोली प्रक्रिया के तहत है।

संभल जिले की शाही जामा मस्जिद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की

नई दिल्ली (ईएमएस) । पश्चिमी उत्तरप्रदेश के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में निचली अदालत के सर्वे के आदेश को चुनौती दी गई है और फैसले पर तुरंत रोक लगाने की अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि यह असाधारण मामला है, इसलिए अदालत असाधारण कदम उठाया जाए। अब सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी। संभल में अदालत के आदेश पर 19 नवंबर को जामा मस्जिद के पहली बार किये गये सर्वेक्षण के बाद से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है। अदालत ने यह आदेश जिस याचिका पर दिया है उसमें दावा किया गया है कि जिस जगह पर जामा मस्जिद है वहां पहले कभी हरिहर मंदिर था।

बीते रविवार को मस्जिद का दोबारा सर्वेक्षण किये जाने के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में 4 लोगों की मौत हो गयी थी और 25 अन्य जख्मी हो गये थे।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दिल्ली में लागू रहेगा जीआरएपी-4

नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से जुड़े मामले को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जीआरएपी-4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) सोमवार तक दिल्ली और एनसीआर में लागू रहेगा! स्कूलों को इससे अलग रखा गया है! कोर्ट ने दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग से नोडल अधिकारी नियुक्त करने को भी कहा, ताकि कोर्ट के कमिश्नर सीधे अपनी शिकायतें उन्हें भेज सकें। जीआरएपी-4 प्रदूषण के खतरनाक स्तर से निपटने के लिए लागू की जाने वाली सख्त योजना है। इसके तहत निर्माण कार्यों पर रोक, ट्रकों की एंट्री बंद और कई अन्य कड़े कदम उठाए जाते हैं। हालांकि, कोर्ट ने यह साफ किया कि स्कूलों को इससे अलग रखा जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर्स ने दिल्ली सरकार से एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग और प्रवर्तन विंग से जुड़ी शिकायतें सीधे नोडल अधिकारी तक पहुंचाई जा सकें। साथ ही कोर्ट कमिश्नर्स की नियुक्ति को जारी रखने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट की प्रदूषण पर नकेल कसने के लिए सभी एजेंसियों को मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं।

विपक्ष पर भड़के गिरिराज ने कहा- सर्वे से क्या दिक्कत है

नई दिल्ली (ईएमएस)। अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली याचिका को स्थानीय अदालत द्वारा सुनवाई के लिए स्वीकार करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी, रामगोपाल यादव समेत कई नेताओं ने इस पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ऐसी अर्जियां आखिर क्यों स्वीकार हो रही हैं। रामगोपाल यादव ने तो विवादित बयान देते हुए कहा कि छोटे-छोटे जज देश में बवाल करा रहे हैं। विपक्ष की अनर्गल बयानबाजी के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इसमें गलत क्या है। उन्होंने कहा कि यदि सर्वे होगा तो क्या दिक्कत है। सच्चाई का पता चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये लोग तो अजमेर को भी संभल बनाना चाहते हैं। संभल में अदालत ने सर्वे कराने का आदेश दिया था। लेकिन फिर भी वहां बवाल में कई लोग मारे गए। आखिर संभल में कोर्ट के फैसले से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। वहां सर्वे ही तो हुआ, लेकिन फिर भी इतना बवाल किया गया। बता दें कि अजमेर सरीफ दरगाह को लेकर हिंदू सेना नाम के संगठन की ओर से एक अर्जी दाखिल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि दरगाह को एक शिव मंदिर के ऊपर बनाया गया है। कोर्ट की ओर से अर्जी स्वीकार करने के बाद से ही विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। अजमेर की स्थानीय अदालत में हिंदू सेना के लीडर विष्णु गुप्ता की ओर से अर्जी दाखिल की गई है। इसमें एक पुस्तक के हवाले से दावा किया गया है दरगाह से पहले यहां मंदिर था और उसका विध्वंस करके ही दरगाह बनी है। ऐसे में अदालत को इसका सर्वे करने का आदेश देना चाहिए। याचिका को जज मनमोहन ने सुनवाई के योग्य माना है और सरकार, एएसआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

पीएम मोदी को मिली जान से मारने की धमकी, धमकी देने वाली महिला मानसिक रूप से अस्थिर

नई दिल्ली (ईएमएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुरुवार को जान से मारने की धमकी दी गई। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में धमकी भरा फोन आया था। जिसके बाद मामले में पुलिस ने एक 34 साल की महिला को हिरासत में लिया। पूछताछ में सामने आया हैं कि महिला मानसिक रूप से अस्थिर है। महिला ने शरारत में फोन किया था। महिला का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। मामले की जांच जारी है।

पीएम मोदी को 6 साल में तीन धमकियां मिलीं

2023 में हरियाणा के शख्स ने वीडियो वायरल कर पीएम मोदी को गोली मारने की धमकी दी थी। वीडियो में युवक ने खुद को हरियाणा का बदमाश और गांव मोहाना निवासी बताया था। वीडियो में युवक ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे सामने आ जाएं, तब मैं गोली मार दूंगा।

2022 में पीएम मोदी को जेवियर नाम के एक शख्स ने धमकी दी थी। जेवियर ने केरल भाजपा अध्यक्ष के. सुरेंद्रन को खत में जान से मारने की धमकी देकर लिखा था कि मोदी का हाल राजीव गांधी जैसा होगा। उस वक्त पीएम केरल दौरे पर जा रहे थे। बाद में पुलिस ने धमकी देने वाले को अरेस्ट कर लिया था।

वहीं 2018 में महाराष्ट्र के मोहम्मद अलाउद्दीन खान नाम के शख्स ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी जो जान से मारने की धमकी दी थी। शख्स ने खुद को आतंकी संगठन जैश-ए -मोहम्मद का सदस्य बताकर देश के पांच प्रमुख शहरों में विस्फोट करने की बात कही थी।

एसपीजी के कंधों पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा देश के पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी की होती है। प्रधानमंत्री के चारों ओर पहला सुरक्षा घेरा एसपीजी जवानों का ही होता है। पीएम की सुरक्षा में लगे इन जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाती है। इनके पास एनएमएफ-2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन और 17 एम रिवॉल्वर जैसे मॉडर्न हथियार होते हैं।

आंध्रप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने अदाणी समूह पर लगे अमेरिकी आरोपों को खारिज किया

हैदराबाद (ईएमएस) । आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने अदाणी समूह पर लगे अमेरिकी आरोपों को खारिज किया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि यह सौदा दो सरकारी एजेंसियों के बीच था। इसमें अदाणी समूह सहित कोई निजी पक्ष शामिल नहीं था। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि रिश्वत के आरोप महज अफवाह हैं। किसी ने यह नहीं कहा है कि मैंने या किसी ने (रिश्वत) ली है।

आंध्रप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने कहा कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा सहित कई राज्यों को 2।49 रूपये प्रति यूनिट पर बिजली की पेशकश की। राज्य को कुछ छूट सहित अन्य प्रोत्साहन भी दिए गए थे, जिससे सरकारी धन की बचत होती। उन्होंने आरोप को गलत बताया है।

वाईएसआरसीपी प्रमुख ने कहा कि अनुबंध एसईसीआई, आंध्रप्रदेश सरकार और राज्य बिजली वितरण कंपनी के बीच था। किसी अन्य एजेंसी के हस्तक्षेप का कोई सवाल ही नहीं था। उन्होंने कहा कि राजनीतिक उद्देश्यों से कुछ मीडिया हाउस रिश्वतखोरी का संकेत देने वाले नाम सामने ला रहे हैं और वह ईनाडु और आंध्र ज्योति पर 100 करोड़ रुपये का मुकदमा करेंगे, जिसे उन्होंने मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू द्वारा नियंत्रित बताया है।

50 आतंकी ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी

जम्मू कश्मीर(ईएमएस)। जम्मू कश्मीर में संदिग्ध आतंकवादियों और उनके समर्थकों की धरपकड़ के लिए गुरुवार को पुलिस ने 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें से अकेले कठुआ जिले के करीब 17 ठिकानों पर छापेमारी कर 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये आतंकियों की मदद करते थे। इनके पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त की गई है। जम्मू रीजन के एडीजे आनंद जैन ने बताया कि पुलिस आतंकवादियों का समर्थन करने वाले कई संदिग्धों के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ कर रही है घाटी में पिछले दिनों हुए आतंकवादी हमलों के जवाब में ये कार्रवाई की जा रही है।

आईआईटी कानपुर ने बनाया गायब होने वाला कपड़ा

सैनिक बन जाएंगे मिस्टर इंडिया, अदृश्य हो जाएंगे फाइटर जेट

नई दिल्ली(ईएमएस)। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने ऐसा कपड़ा बनाया है, जिसके पीछे जाते ही न तो सैनिक दिखता है। न ही कोई अन्य मटेरियल। यानी इस महा-मैटेरियल का इस्तेमाल भारतीय सेना करने लगे तो हमारे सैनिक मिस्टर इंडिया बन जाएंगे। साथ ही जरूरी हथियार भी छिपे रहेंगे। ये एक मेटामैटेरियल सरफेस क्लोकिंग सिस्टम है। जो हमारे सैनिकों, विमानों और ड्रोन्स को दुश्मनों से बचा सकता है। इस कपड़े का फायदा ये है कि ये न तो दुश्मन की राडार की पकड़ में आता है। न सैटेलाइट की। इसे इंफ्रारेड कैमरा, वूंड सेंसर्स और थर्मल इमेजर से भी नहीं देख सकते। यानी इस मैटेरियल से के पीछे क्या है किसी को पता ही नहीं चलेगा।

अगर आप इस तस्वीर में दाहिनी ओर लगे थर्मल इमेजर में देखें तो कपड़े के पीछे इंसान नहीं दिख रहा है। सिर्फ उसका सिर और हाथ दिख रहा है। यानी कपड़े के पीछे जो हिस्सा है वो एकदम नहीं दिखेगा। इस कपड़े से सैन्य गाड़ियों के कवर, सैनिकों के यूनिफॉर्म, या एयरक्राफ्ट कवर बनाया जा सकता है। यह कपड़ा पूरी तरह से स्वदेशी है। साथ ही विदेशों से मंगाए जाने वाले सरफेस क्लोकिंग सिस्टम से 6-7 गुना ज्यादा सस्ता भी है। आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर प्रो। मनिंद्र अग्रवाल ने इस मेटामैटेरियल का उद्घाटन किया।

किसी भी तकनीक से नहीं दिखेंगे सैनिक

इस कपड़े का प्रदर्शन आईआईटी कानपुर में हुए डिफेंस स्टार्टअप एग्जीबिशन में भी किया गया था। जहां पर इसकी काफी प्रशंसा हुई। अगर इस कपड़े को आर्मी की गाड़ियों के चारों तरफ लगा दिया जाए। सैनिकों को इसका यूनिफॉर्म दिया जाए तो वो दुश्मन के किसी भी प्रकार के कैमरे में ट्रैक नहीं होंगे। न ही किसी इमेजिंग सिस्टम में। न ही सेंसर में। इससे दुश्मन की कई तकनीक को विफल किया जा सकता है। आईआईटी के तीन साइंटिस्ट प्रो। कुमार वैभव श्रीवास्तव, प्रो। एस अनंत रामकृष्णन और प्रो। जे। रामकुमार ने मिलकर इस मेटामैटेरियल को तैयार किया है। इसके पेटेंट के लिए 2018 में एप्लीकेशन दिया गया था। जो अब इन्हें मिल चुका है। इस तकनीक का ट्रायल भारतीय सेना के साथ छह साल से हो रहा है।

किसी भी तरह की तकनीक को दे सकता है धोखा

प्रो. कुमार वैभव ने 2010 से इस पर काम करना शुरू किया था। इसके बाद दोनों प्रोफेसर इनके साथ जुड़ गए। फिर यह प्रोडक्ट तैयार हुआ। 2019 में भारतीय सेना ऐसी तकनीक खोज रही थी, जिससे दुश्मन के राडार को चकमा दिया जा सके। फिर इसे तैयार किया गया। यह मैटेरियल दुश्मन के राडार, सैटेलाइट, इंफ्रारेड कैमरा, ग्राउंड सेंसर और थर्मल इमेजर को धोखा दे सकता है। मेटातत्व कंपनी के एमडी और पूर्व एयर वाइस मार्शल प्रवीण भट्ट ने कहा कि अगर अप्रूवल मिले तो यह मैटेरियल हम भारतीय सेना को एक साल में दे सकते हैं। यह किसी भी तरह के इमेजिंग प्रोसेस को रोकने में सक्षम है।

जन हितैषी

शिक्षकों और पुलिस के 13 लाख रेलवे के 2.63 लाख सरकारी पद कई वर्षों से खाली

प्रत्येक राज्य में विभिन्न विभागों के लाखों सरकारी पद पिछले कई वर्षों से खाली पड़े हैं। सरकारी पदों को भरने के लिए समय-समय पर परीक्षाओं का आयोजन भी किया जा रहा है। परीक्षा के पेपर लीक होने की घटनाएं सभी राज्यों में बढ़ती चली जा रही हैं। परीक्षा आयोजित करना और युवाओं से करोड़ों रुपए की फीस वसूल करना यह एक धंधा बन गया है। अकेले एक राज्य में पेपर लीक नहीं हो रहे हैं। लगभग सभी राज्यों में यही स्थिति देखने को मिल रही है। परीक्षाएं निजी एजेंसियों द्वारा आयोजित कराई जा रही हैं। उसके जरिए अवैध रूप से कमाई करने का एक नया रास्ता निकाला गया है। जिसके कारण सारी गड़बड़ियाँ हो रही हैं। संसद में शिक्षा मंत्रालय की जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है उसके अनुसार राजस्थान में आठ बार, उत्तर प्रदेश में आठ बार, महाराष्ट्र में सात बार, बिहार में छह बार, मध्य प्रदेश में चार बार, गुजरात में चार बार, हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 3-3 बार, दिल्ली, मणिपुर, तेलंगाना मे दो-दो बार तथा हिमाचल, उत्तराखंड, झारखंड, नागालैंड, आसाम में एक-एक बार परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं। जिन परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, उनमें शिक्षक भर्ती और पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर सबसे ज्यादा हैं।

शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 8.46 लाख पद विभिन्न राज्यों में शिक्षकों के खाली पड़े हुए हैं। गृह मंत्रालय के डेटा के अनुसार पुलिस विभाग में 4.33 लाख पद पिछले कई वर्षों से खाली पड़े हुए हैं। संसद में दी गई जानकारी के अनुसार यह आंकड़ा 1 जनवरी 2023 तक का है। इस बीच लाखों की संख्या में कर्मचारी और शिक्षक रिटायर हुए हैं। वह पद भी नहीं भरे गए हैं। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया की 2014-15 से लेकर 2021-22 के बीच में सरकारी पदों के लिए 22 करोड़ युवाओं ने आवेदन किए थे। सरकार के अनुसार 7.22 लाख लोगों को चयनित किया गया है। परीक्षा में जो छात्र चयनित हो गए हैं, उनकी नियुक्ति भी विभिन्न कारणों से रोक कर रखी गई है। चयनित हो जाने के कई वर्षों बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। किसी न किसी गड़बड़ी के कारण चयनित परीक्षार्थियों को जॉइनिंग नहीं दी जा रही है। चयनित छात्रों से अवैध रूप से राशि वसूल कर टुकड़े-टुकड़े में उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार 9.64 लाख पद केंद्र सरकार के खाली पड़े हुए हैं। रेलवे के भी करीब 2.63 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। सरकार इन पदों को क्यों नहीं भर रही है। इसको लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। रेलवे के बारे में कहा जाता है, सरकार रेलवे को निजी क्षेत्र को सौंपना चाहती है। इस कारण रेलवे भर्ती नहीं कर रहा है। सभी जगह संविदा और ठेके पर नौकरी दी जा रही है। सरकार पिछले कई वर्षों से रिक्त पदों को नहीं भर रही है। समय-समय पर परीक्षा आयोजित की जाती है। लाखों विद्यार्थी परीक्षा में बैठते हैं। अरबों रुपए की कमाई परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों को हो रही है। अधिकांश मामलों में पेपर लीक हो जाने के कारण सारा मामला टल जाता है। पिछले कई वर्षों से यही सब कुछ हो रहा है। जिसके कारण युवाओं में स्पष्ट रूप से नाराजी देखने को मिलने लगी है। सरकार जो दावे करती है। वह हकीकत से दूर होते हैं। मोदी सरकार अच्छे दिन के वादे और 2 करोड़ नौकरी देने के वादे के साथ केंद्र की सत्ता में आई थी। सभी को विश्वास था, मोदी जी ने जो कहा है, वह जरूर पूरा करेंगे। 2014 के चुनाव में उन्होंने 60 माह का समय मांगा था। लोगों की आशा और विश्वास मोदी जी पर बन गया था। 2019 में आम मतदाताओं ने उन्हें पुनः प्रचंड बहुमत से जिताकर मौदी पर विश्वास किया था। युवाओं को विश्वास था, उनकी नौकरी लगेगी। सरकार के खाली पद भरे जाएंगे। लेकिन लंबे समय तक नौकरी नहीं मिलने के कारण करोड़ युवाओं की उम्र ज्यादा हो चुकी है। सरकारी नौकरी के लिए उनकी पात्रता ही नहीं बची है। युवाओं में जिस तरीके की हताशा और निराशा देखने को मिल रही है। बार-बार पेपर लीक हो रहे हैं। परीक्षाओं में चयन हो जाने के बाद नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। उसके कारण अब युवाओं के बगावती तेवर सड़कों पर दिखने लगे हैं। प्रयागराज की घटना से केंद्र एवं राज्य सरकारों को सबक लेने की जरूरत है। 1975 का छात्र आंदोलन, जेपी के सफल आंदोलन और आपातकाल का कारण बना। लगभग वैसी ही स्थिति अब देश भर में बनती हुई दिख रही है। पिछले 10 वर्षों से रिक्त पदों को भरने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों ने कोई ठोस प्रयास नहीं किए हैं। पुलिस और शिक्षक के पद खाली पड़े हुए हैं। रेलवे जो सबसे ज्यादा नौकरी उपलब्ध कराती थी, अब वहां पर भी भरती नहीं हो रही है। सारे काम ठेके पर दिए जा रहे हैं, जिसके कारण युवा विद्रोही होकर सड़कों पर उतर रहे हैं। छात्रों ने जो भी आंदोलन शुरू किया है। जब तक वह मुकाम तक नहीं पहुंचता है। तब तक वह शांत नहीं बैठते हैं। अन्ना आंदोलन में जिस तरह से युवा आंदोलन का सूत्रधार बने थे। जिसके कारण देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। लगभग वही स्थिति एक बार फिर से निर्मित होती हुई दिख रही है। महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याओं का समाधान तुरंत नहीं खोजा गया, तो इसके भारी दुष्परिणाम निकट भविष्य में देखने को मिल सकते हैं।

संभल की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से उपजे जटिल सवाल

यह दुर्भाग्यपूर्ण एवं त्रासद है कि उत्तर प्रदेश के संभल में एक बार फिर एक सम्प्रदाय विशेष के लोगों ने जो हिंसा, नफरत एवं द्वेष को हथियार बनाकर अशांति फैलायी, वह भारत की एकता, अखण्डता एवं भाईचारे की संस्कृति को क्षति पहुंचाने का माध्यम बनी है। स्थानीय अदालत के आदेश पर एक मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा एवं उन्माद का भड़क उठना और इसके चलते तीन लोगों की जान चले जाना, चुनौतीपूर्ण, विडम्बनापूर्ण एवं शर्मनाक है। इस घटना में कई अन्य लोग घायल भी हुए, जिनमें 30 से अधिक पुलिसकर्मी भी हैं। इस हिंसा को टाला जा सकता था यदि अदालत के आदेश पर हो रहे सर्वेक्षण का हिंसक विरोध नहीं किया जाता। ध्यान रहे कि जब ऐसा होता है तो बैर बढ़ने के साथ देश की छवि पर भी बुरा असर पड़ता है। निःसंदेह इस सम्प्रदाय विशेष को भी यह समझने की आवश्यकता है कि जब देश कई चुनौतियों से दो-चार है, तब राष्ट्रीय एकता एवं सद्भाव को बल देना सबकी पहली और साझी प्राथमिकता बननी चाहिए। एक उन्मादी, विभाजित और वैमनस्यग्रस्त समाज न तो अपना भला कर सकता है और न ही देश को आगे ले जा सकता है। समय आ गया है कि उन मूल कारणों पर विचार किया जाए, जिनके चलते साम्प्रदायिक तनाव, नफरत एवं द्वेष बढ़ाने वाली घटनाएं थम नहीं रही हैं।

संभल की स्थानीय अदालत ने उस याचिका पर जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि मुगल बादशाह बाबर ने इस मस्जिद का निर्माण एक मंदिर के स्थान पर किया था। स्थानीय अदालत के आदेश पर इसी मंगलवार को जब प्रारंभिक सर्वे किया गया था तब भी इलाके में तनाव फैला था, लेकिन उसे दूर कर लिया गया था। समझना कठिन है कि गत दिवस सर्वे के दौरान ऐसे प्रयास क्यों नहीं किए गए जिससे किसी तरह की अव्यवस्था और अशांति न फैलने पाए। रविवार को सर्वे के दौरान जिस तरह पुलिस पर पथराव किया गया और वाहनों में तोड़फोड़ करने के साथ उन्हें आग के हवाले किया गया, उससे लगता है कि कुछ उन्मादी तत्वों ने उपद्रव की तैयारी कर रखी थी। ऐसी घटनाएं सामाजिक तानेबाने को क्षति पहुंचाने के साथ कानून एवं व्यवस्था के समक्ष चुनौती भी खड़ी करती हैं। यह चिंता की बात है कि यह एक चलन सा बनता जा रहा है कि जब सार्वजनिक स्थलों पर कोई धार्मिक आयोजन होता है, किसी अदालती आदेश पर जांच कार्य होता है तो प्रायः पहले किसी बात को लेकर विवाद होता है और फिर हिंसा शुरू हो जाती है। कई बार तो यह हिंसा बड़े पैमाने पर और किसी सुनियोजित साजिश के तहत होती दिखती है। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई भीषण हिंसा यही संकेत करती है कि उसे लेकर पूरी तैयारी की गई थी।

संभल की ताजा घटनाओं के मूल में भड़काऊ नारे एवं संकीर्ण धार्मिकता के मनसूबे सामने आये हैं। इस तरह की घटनाओं का बार-बार होना अच्छा नहीं है, मंदिर-मस्जिद के एक और मामले ने तनाव की स्थिति उत्पन्न करके शांति एवं सौहार्द को खण्डित किया। यदि मस्जिद पक्ष का यह मानना है कि जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश सही नहीं तो उसे ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। अदालत के आदेश की अवहेलना करने के लिए हिंसा का सहारा लेने का कहीं कोई औचित्य नहीं और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब निचली अदालत के किसी फैसले के खिलाफ ऊंची अदालतों में जाने का रास्ता खुला हो। यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या कुछ राजनीतिक दल एवं सम्प्रदाय विशेष के लोग किसी भी बहाने भड़काने और हिंसा करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं? वास्तव में जैसे यह एक सवाल है कि क्या भारतीय संस्कृति के अस्तित्व एवं अस्मिता से जुड़े इन धार्मिक स्थलों के नाम पर पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी करना जरूरी समझ लिया गया है? इन प्रश्नों पर संकीर्ण धार्मिकता से परे होकर गंभीरता के साथ विचार होना चाहिए। इसी तरह पुलिस प्रशासन को भी यह देखना होगा कि वैमनस्य बढ़ाने वाली घटनाएं क्यों बढ़ती चली जा रही हैं?

यह सही है कि 1991 का पूजा स्थल अधिनियम किसी धार्मिक स्थल में बदलाव का निषेध करता है, लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि यह अधिनियम ऐसे किसी स्थल के सर्वेक्षण की अनुमति भी प्रदान करता है और इसी कारण वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण हुआ और धार में भोजशाला परिसर का भी। मथुरा में ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। मंदिर-मस्जिद के विवाद नए नहीं हैं। इन विवादों को सुलझाने की आवश्यकता है। इसका एक तरीका न्यायपालिका का सहारा लेना है और दूसरा आपसी सहमति से विवाद को हल करना। इससे बेहतर और कुछ नहीं कि जहां भी ऐसे विवाद हैं, उन्हें दोनों समुदाय आपस में मिल-बैठकर हल करें। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि समाज में सद्भाव, सौहार्द एवं शांति बनी रहेगी। यह समझा जाना चाहिए कि इन दोनों उपायों के अतिरिक्त हिंसा एवं उन्माद कोई उपाय नहीं है। इसी के साथ यह भी समझना होगा कि देश को अतीत से अधिक भविष्य की ओर देखने और मंदिर-मस्जिद विवादों से बाहर निकलने की आवश्यकता है। इससे इन्कार नहीं कि विदेशी आक्रमणकारियों ने अनगिनत मंदिरों का ध्वंस किया। अतीत में हुए इन ज्यादतियों, अत्याचारों एवं विध्वंस घटनाक्रमों को सुधारने की संभावनाएं किसी भी दृष्टि से गलत नहीं कही जा सकती।

देश का चरित्र बनाना है तथा स्वस्थ, सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्ण समाज की रचना करनी है तो हमें एक ऐसी आचार संहिता को स्वीकार करना होगा जो जीवन में पवित्रता दे। राष्ट्रीय प्रेम व स्वस्थ समाज की रचना की दृष्टि दे एवं कदाचार-संकीर्णता-कट्टरता के इस अंधेरे कुएँ से निकाले। बिना इसके देश का विकास और भौतिक उपलब्धियां बेमानी हैं। व्यक्ति, परिवार और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे इरादों की शुद्धता महत्व रखती है, जबकि हमने इसका राजनीतिकरण कर परिणाम को महत्व दे दिया। घटिया उत्पादन के पर्याय के रूप में जाना जाने वाला जापान आज अपनी जीवन शैली को बदल कर उत्कृष्ट उत्पादन का प्रतीक बन विश्वविख्यात हो गया। यह राष्ट्रीय जीवन शैली की पवित्रता का प्रतीक है। इसी तरह भारत भी आज विश्वविख्यात होने की दिशा में अग्रसर हो रहा है, तो उसकी बढ़ती साख एवं समझ को खण्डित करने वाली शक्तियों को सावधान करना ही होगा। भारत जैसी माटी में जन्म लेना बड़ी मुश्किल से मिलता है। विश्व बंधुत्व एवं वसुधैव कुटुम्बकम की विचारधारा वाला यह राष्ट्र विभिन्न संस्कृतियों एवं सम्प्रदायों को अपने में समेटे है तो यह यहां के बहुसंख्यक समुदाय की उदार सोच का ही परिणाम रहा है, इसी बहुसंख्यक हिन्दू समुदाय को आखिर कब तक कमजोर किया जाता रहेगा? क्यों किया जायेगा? कल पर कुछ मत छोड़िए। कल जो बीत गया और कल जो आने वाला है- दोनों ही हमारी पीठ के समान हैं, जिसे हम देख नहीं सकते। आज हमारी हथेली है, जिसकी रेखाओं को हम देख सकते हैं। अब हथेली की रेखाओं को कमजोर करने एवं उसे लहूलुहान होते हुए नहीं देखा जा सकता?

एक सम्प्रदाय विशेष के हिंसक हमलों ने आज तेजी के साथ हिंसा, असहिष्णुता, नफरत, बिखराव और घृणा की साम्प्रदायिक जीवन शैली का रूप ग्रहण कर लिया है। यह खतरनाक स्थिति है, कारण सबको अपनी-अपनी पहचान समाप्त होने का खतरा दिख रहा है। भारत मुस्लिम सम्प्रदायवाद से आतंकित रहा है। आवश्यकता है धर्म को प्रतिष्ठापित करने के बहाने राजनीति का खेल न खेला जाए। धर्म और सम्प्रदाय के भेद को गड्मड् न करें। धर्म सम्प्रदाय से ऊपर है। धर्म में धार्मिकता आये, कट्टरता न आये। राजनीति में सम्प्रदाय न आये, नैतिकता आए, आदर्श आए, श्रेष्ठ मूल्य आएँ, सहिष्णुता आये, सह-अस्तित्व के प्राचीन मूल्य एवं जीवनशैली आये। अतः सम्प्रदायवाद से ऊपर उठकर सार्वभौम धर्म को साक्षात्कार करना हमारे लक्ष्य हो। सशक्त भारत-विकसित भारत का संचार करेगा। उपनिषदों में कहा गया है कि सभी मनुष्य सुखी हों, सभी भयमुक्त हों, सभी एक-दूसरे को भाई समान समझें। यह भारतीय धर्म चिन्तन का निचोड़ है और यही हिन्दू धर्म का निचोड़ है। जहां विश्व एक ही नीड़-सा लगे। भारत में हिन्दू-मुस्लिम हित परस्पर टकरा रहे हैं, इसलिए साम्प्रदायिकता बढ़ रही है। धार्मिकता नष्ट हो रही है। साम्प्रदायिकता का जन्म अनेक जटिल तत्वों से जुड़ा है - आर्थिक, धार्मिक एवं मनोवैज्ञानिक। इसमें मनोवैज्ञानिक ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा जीवन दिशासूचक बने। गिरजे पर लगा दिशा-सूचक नहीं, वह तो जिधर की हवा होती है उधर ही घूम जाता है। कुतुबनुमा बने, जो हर स्थिति मे सही दिशा बताता है।(लेखक - ललित गर्ग/ ईएमएस)(लेखक, पत्रकार, स्तंभकार)

अब अजमेर वाले ख्वाजा साहब की बारी

देश की संसद तीन दिन से ठप्प है ,लेकिन ये कोई खबर नहीं है । खबर ये है कि देश की 6 लाख मस्जिदों और दरगाहों पर कब्जा हासिल करने के महा अभियान के तहत अब अजमेर वाले ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह हम हिन्दुओं के निशाने पर है। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करते हुए अजमेर सिविल कोर्ट में लगाई गई याचिका को कोर्ट ने सुनने योग्य माना है। यह याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से याचिका लगाई गई।

आपको पता ही होगा कि राजस्थान राज्य के अजमेर में स्थित ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भारत के प्रमुख तीर्थस्थलों में से एक है। यह दरगाह, गुलाबी शहर जयपुर से करीब 135 किलोमीटर दूर, चारों तरफ अरावली की पहाड़ियों से घिरे अजमेर शहर में स्थित है। अजमेर शरीफ की दरगाह के नाम से यह पूरे देश में प्रसिद्ध है।इस दरगाह से सभी धर्मों के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसे सर्वधर्म सद्भाव की अदभुत मिसाल भी माना जाता है। ख्वाजा साहब की दरगाह में हर मजहब के लोग अपना मत्था टेकने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी ख्वाजा के दर पर आता है कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता है, यहां आने वाले हर भक्त की मुराद पूरी होती है।

देश के भाग्यविधाता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का तो पता नहीं, लेकिन ख्वाजा की मजार पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू,भाजपा के दिग्गत नेता और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी,अमेरिका कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत कई नामचीन और मशहूर शख्सियतों ने अपना मत्था टेका है। आप इस फेहरिश्त में मेरा नाम भी बाबस्ता कर सकते हैं । मैं भी दो मर्तबा इस दरगाह पर सपरिवार माथा टेक आया हूँ,हालाँकि मैं पक्का सनातनी हूँ। ख्वाजा के दरबार में अक्सर बड़े-बड़े राजनेता एवं अभिनेता आते रहते हैं और अपनी अकीदत के फूल पेश करते हैं एवं आस्था की चादर चढ़ाते हैं। अपने अनेक फिल्मों में इस दरगाह को देखा होगा।

तकरीबन 559 साल पुरानी इस दरगाह को लेकर अजमेर के न्यायालय ने वाद को स्वीकार करते हुए दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मामलात व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण धरोहर को नोटिस जारी करने के आदेश जारी करने का फैसला दिया है। वादी विष्णु गुप्ता की ओर से हरदयाल शारदा की ओर से लिखी पुस्तक का हवाला देते हुए वाद प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उन्होंने अजमेर की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर 2024 को की जाएगी।मुमकिन है कोई शंकराचार्य इस मामले में गवाह बनकर पेश हो जाये।

हम हिन्दुओं की नई पीढ़ी बहुत जागरूक है इसलिए जो काम उनके पुरखे पांच सौ साल पहले नहीं कर पाए,उसे वे अब अंजाम दे रहे है।याचिकाकर्ता का दावा है कि दरगाह की जमीन पर पहले भगवान शिव का मंदिर था। मंदिर में पूजा और जलाभिषेक होता था। याचिका में अजमेर निवासी हर विलास शारदा द्वारा वर्ष 1911 में लिखी पुस्तक का हवाला दिया गया है। पुस्तक में दरगाह के स्थान पर मंदिर का जिक्र है।पुस्तक कहती है की दरगाह परिसर में मौजूद 75 फीट लंबे बुलंद दरवाजे के निर्माण में मंदिर के मलबे के अंश तहखाने में गर्भगृह होने का प्रमाण मिल जाएगा।

ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की इस दरगाह को मंदिर बताते हुए इससे पहले हिंदू सेना की तरफ से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिका पेश की गई थी। हालांकि, न्यायाधीश प्रीतम सिंह ने ये कहकर सुनवाई से इनकार कर दिया था कि यह उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। इसके बाद जिला अदालत में याचिका पेश की गई। मुझे लगता है कि इस तरह की फुटकर याचिकाओं पर सुनवाई के बजाय अब खुद सरकार को याचिकाकर्ता बनकर देश की तमाम मस्जिदों,दरगाहों, ईदगाहों और ताजमहल तक का सर्वे करने के लिए अदालत से दरख्वास्त करना चाहिए ,क्योंकि हम हिन्दुओं का पक्का विश्वास है कि हर मस्जिद,दरगाह और ईदगाह के नीचे कोई न कोई मंदिर जरूर है।

अयोध्या की बाबरी मस्जिद को गिराने से शुरू हुआ ये अभियान बीच में थम गया था लेकिन अब एक के बाद एक शहर में ऐसी याचिकाएं लगाईं जा रहीं है। पहले ज्ञानवापी का सर्वे हुआ । फिर संभल में सर्वे हो चुका है और दंगा भी सम्भल में 4 लोग मारे भी जा चुके हैं । अब मथुरा और अजमेर की बारी है। अजमेर की दरगाह में पड़े-पड़े ख्वाजा साहब भी शायद उकता गए होंगे। सरकार को चाहिए की वो देश में मौजूद उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर अजमेर की दरगाह को जमीन से निकलकर नीलम कर दे । दुनिया का कोई न कोई इस्लामिक देश ख्वाजा साहब की दरगाह को खरीद लेगा और अपने मुल्क में ससम्मान स्थापित कर लेगा

इस मुद्दे पर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी भड़के हुए है, जिसमें उन्होंने सरकार और अदालतों के कानूनी कर्तव्यों पर सवाल उठाए हैं। आजकल सवाल संसद सेमें हंगामे के कारण उठाये नहीं जा सकते,इसलिए ये सवाल एक्स के पटल पर उठाये जाते हैं। एक्स का पटल संसद से ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। ओवैसी ने एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, सुल्तान-ए-हिन्द ख़्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के मुसलमानों के सबसे अहम औलिया इकराम में से एक हैं. उनके आस्तान पर सदियों से लोग जा रहे हैं और जाते रहेंगे इंशाअल्लाह. कई राजा, महाराजा, शहंशाह, आए और चले गये, लेकिन ख़्वाजा अजमेरी का आस्तान आज भी आबाद है। उन्होंने कहा कि 1991 का इबादतगाह कानून साफ तौर पर यह कहता है कि किसी भी इबादतगाह की मजहबी पहचान को नहीं बदला जा सकता. ओवैसी ने यह भी आरोप लगाया कि हिंदुत्व तंजीमों का एजेंडा पूरा करने के लिए कानून और संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर चुप है।

अब ओवैसी को कौन समझाये कि हमारे वजीरेआजम हर संवेदनशील मुद्दे पर चुप ही रहते है। वे मणिपुर के मामले पर आखिर डेढ़ साल से चुप ही हैं न ? वजीरेआजम केवल तभी बोलते हैं जब उन्हें अपने मन की बात करना होती है । वे तभी बोलते हैं जब उनके घर के बंद कमरे में उनके सामने कैमरा हो। वे संसद में चुने हुए प्रतिनिधियों के सामने नहीं बोलते। उन्हें निर्वाचित सांसद गुंडे ,मवाली नजर आते हैं। तकलीफ की बात ये है कि केंद्र की सरकार ऐसे प्रयासों का संज्ञान ही नहीं ले रही बल्कि उनका साथ दे रही है। सरकार ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है की इस तरह गड़े मुर्दे उखाड़ने से देश के सद्भाव को भारी नुक्सान हो रहा है। यदि सरकार मुस्लिम आस्थाओं का सम्मान कर रही होती तो खुद देश की सबसे बड़ी अदालत में खड़ी होकर दरख्वास्त करती की देश में किसी भी धार्मिक स्थल के सर्वे की किसी याचिका को मजूर न किया जाये। लेकिन मोदी युग में ये होना नामुमकिन है। इस युग में जो होना चाहिए वो ही तो हो रहा है।

जग-जाहिर है की ख़्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती एक प्रसिद्ध सूफ़ी संत होने के साथ-साथ इस्लामिक विद्वान और दार्शनिक थे।उनकी ख्याति इस्लाम के महान उपदेशक के रूप में भी विश्व भर में फैली हुई थी। उन्होंने अपने महान विचारों और शिक्षाओं का प्रचार-प्रसार किया एवं उन्हें भारत में इस्लाम का संस्थापक भी माना जाता था। उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता था। उनकी अद्भुत एवं चमत्कारी शक्तियों की वजह से वे मुगल बादशाहों के बीच भी काफी लोकप्रिय हो गए थे।उन्होंने अपने गुरु उस्मान हरूनी से मुस्लिम धर्म की शिक्षा ली एवं इसके बाद उन्होंने धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए कई यात्राएं की एवं अपने महान उपदेश दिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने पैदल ही हज यात्रा की थी। ऐसा माना जाता है कि करीब 1192 से 1195 के बीच में वे मदीना से भारत यात्रा पर आए थे, वे भारत में मुहम्मद से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे, ख्वाजा साहब भारत आने के बाद शुरुआत में थोड़े दिन दिल्ली रुके और फिर लाहौर चले गए, एवं अंत में वे मुइज़्ज़ अल- दिन मुहम्मद के साथ अजमेर आए और यहां की वास्तविकता से काफी प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने अजमेर रहने का ही फैसला लिया।

बहरहाल मेरा मश्विरा है कि यदि आपने ये दरगाह न देखी हो तो फौरन वक्त निकलकर देखा आएं,क्या पता आने वाले दिनों में ये दरगाह रहे भी या न रहे। यहां फिर नए सिरे से कोई मंदिर तामीर कर दिया जाये। यही बात आगरा के ताजमहल के बारे में लागू होती है । किस दिन कोई सिरफिरी भीड़ ताजमहल को भी नेस्तनाबूद कर सकती है।(लेखक-राकेश अचल/ईएमएस

तो यह है विश्व गुरु भारत में इंसानी जान की क़ीमत ?

सत्ता, गोदी मीडिया व अंधभक्तों की जमाअत संयुक्त रूप से भारत को विश्वगुरु साबित करने के लिये एड़ी चोटी का ज़ोर लगाये हुये है। 7 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ज्ञान व उसकी विचारधारा को भारतीय शिक्षा से जोड़ने का अथक प्रयास करने वाले,शिक्षा बचाओ आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक दीनानाथ बत्रा का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे एक राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था विद्या भारती के महासचिव भी थे। बत्रा ने अपना सारा जीवन इसी तरह की बातों को सही साबित करने की कोशिशों में खपा दिया कि हवाई जहाज़ का अविष्कार राइट ब्रदर्स ने नहीं किया बल्कि यह भारतीय पौराणिक काल की उपलब्धि थी। इसी तरह टेलीविज़न के अविष्कार को वे वर्तमान आधुनिक विज्ञान की देन नहीं मानते थे बल्कि इसे महाभारतकाल के पहले की भारतीय खोज बताते थे। ऐसे सैकड़ों विज्ञान सम्मत बातों पर उनके निजी विचार भले ही विश्व स्वीकार्य हों या न हों परन्तु भारत को कथित तौर से विश्वगुरु साबित करने के दिशा में ही एक उठाये गये क़दम थे।

परन्तु भारत को पुनः विश्वगुरु के रूप में विश्व में स्थापित करने की इन्हीं कोशिशों के बीच शायद हम यह भूल जाते हैं कि विश्व का नेतृत्व करने की आकांक्षा रखने वाले हमारे देश के अपने नागरिकों की जान माल आख़िर कितनी सुरक्षित है ? और दशकों से इंसानी जान से खिलवाड़ करने वाली ऐसी कमज़ोर कड़ियों से निपटने का हमने अब तक क्या उपाय किया है ? कोई उपाय किया भी है या नहीं ? या सत्ता इस बात को ही अंगीकार कर चुकी है कि बिना सुरक्षित उपायों के ही जब जनता को आसानी से मूर्ख बनाया जा सके तो ऐसे किसी उपायों की ज़रुरत ही क्या है ? मिसाल के तौर पर बोरवेल में बच्चों के गिरने की देश में कितनी घटनाएं हो चुकीं। कहीं जांबाज़ सहायता कर्मियों ने अपने अथक प्रयासों से बच्चे को बोरवेल से बाहर निकाल कर उन्हें बचाया तो कई जगह बच्चों को बचा पाना संभव नहीं हो सका। परन्तु ऐसे ख़बरों का सिलसिला आज भी थमा नहीं है।

कहीं मेन होल टूटने या उसका ढक्कन न होने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है तो कभी इसी मेन होल की सफ़ाई करते समय कोई सफ़ाई कर्मचारी ज़हरीली गैस के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठता है। जगह जगह सड़कों पर बने गड्ढे दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। सांड़,गाय व आवारा कुत्ते तो देश के किसी न किसी भाग में रोज़ाना राहगीरों की जान लेते ही रहते हैं। इन्हीं आवारा पशुओं के कारण अनेक दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कभी कभी तो ट्रेन हादसों की भी झड़ी सी लग जाती है। कभी 30 अक्टूबर 2022 की गुजरात के मोरबी नामक शहर के मच्छु नदी में बने मोरबी पुल टूटने जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होती है जिसमें 141 लोगों की नदी मन बह जाने से मौत हो जाती है। तो कभी अस्पतालों में यहाँ तक कि बच्चों के अस्पतालों में आग लग जाती है जिसमें जीवित शिशु झुलस कर मर जाते हैं। ऑक्सीजन की कमी या अभाव से भी लोगों के मरने की ख़बरें आती ही रही हैं। ऐसे और भी अनेक कारणों से विश्वगुरु देश के वासी स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करते।

इंसान की जान से खिलवाड़ करने वाली सरकारी लापरवाही की ऐसी ही एक दिल दहलाने वाली घटना पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के बरेली के निकट फ़रीदपुर - बदायूं मार्ग पर स्थित राम गंगा नदी पर निर्माणाधीन एक पुल पर हुई। इस निर्माणाधीन पुल का रास्ता किसी अवरोध या संकेत के माध्यम से बंद नहीं किया गया था। उधर गूगल मैप ने भी इसी आधे अधूरे पुल का मार्ग बताया। उसी मार्ग पर शादी से लौट रहे तीन दोस्त अपनी बुलेरो गाड़ी से पूरी रफ़्तार से इसी विश्वास से चल पड़े कि चूँकि पुल का मार्ग खुला है और गूगल मैप भी यह रास्ता सुझा रहा है लिहाज़ा मार्ग चालू ही होगा। परन्तु वह अर्धनिर्मित पुल हवा में लटका हुआ था। नतीजतन तेज़ रफ़्तार बुलैरो नदी में जा गिरी जिससे तीनों दोस्तों की मौक़े पर ही मौत हो गयी और वाहन के भी चीथड़े उड़ गये। इस हादसे के बाद अब जानकारी मिल रही है कि रामगंगा नदी पर पिछले साल सितंबर में संपर्क मार्ग बह जाने के बाद से ही यह पुल अर्धनिर्मित अवस्था में ही पड़ा हुआ है। अब यह भी बताया जा रहा है कि लोक निर्माण विभाग ने रामगंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल से पहले किसी तरह का बैरियर या अवरोध नहीं लगाया था। इस हादसे का ज़िम्मेदार पुल निर्माण करने वाली कंपनी, इसके ठेकेदार व प्रशासन की लापरवाही को भी बताया जा रहा है। वाहनों को पुल पर आने से रोकने के लिए लोगों को सावधान करने की ग़रज़ से यहां कोई बोर्ड, संकेत या सूचना नहीं लगाई गई है अथवा किसी तरह का अवरोध नहीं लगाया गया था। यहाँ तक कि संबंधित विभाग ने गूगल मैप पर रूट में बदलाव भी नहीं करवाया था। अर्थात यह पुल अर्धनिर्मित है इस बात की जानकारी गूगल पर अपडेट नहीं थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में लोक निर्माण विभाग के चार लोगों के ख़िलाफ़ नामज़द मुक़दमा दर्ज हुआ है। पुलिस को दी गई तहरीर में गूगल मैप्स के क्षेत्रीय प्रबंधक को भी ज़िम्मेदार माना गया है। इसी तहरीर में आरोप है कि -लोक निर्माण विभाग के इन अधिकारियों ने जानबूझकर पुल के दोनों किनारों पर मज़बूत बैरिकेडिंग, बैरियर या रिफ़्लेक्टर बोर्ड नहीं लगवाए, न ही रोड के कटे होने की सूचना के बोर्ड आदि लगवाए गए।

बरेली में हुये इस हादसे के बाद जब खोजी पत्रकारों ने दूर दराज़ के ही नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली के कई ऐसे पुल व फ़्लाई ओवर व एक्सप्रेस वे ढूंढ निकाले जो इसी तरह के हादसों को न्यौता देते हैं। इनमें भी कई जगह वाहनों को रोकने के लिये कोई संकेत या अवरोध नहीं है,कहीं पुलों पर गड्ढे हैं। आज़ादपुर,पंजाबी बाग़,रजौरी गार्डन,मयूर विहार जैसे भीड़ भरे और जाम लगने वाले ऐसे इलाक़ों में भी प्रशासनिक लापरवाहियां सर चढ़ कर बोल रही हैं। सच पूछिये तो इन लापरवाहियों के पीछे भी भ्रष्टाचार और प्रशासनिक ग़ैर जवाबदेही ही मुख्य कारण है। इसलिये भले ही हम राम मंदिर जैसे अपने विचारों की आवाज़ों में डूबकर स्वयं को कितना ही महान क्यों न समझने लगें और धर्म रुपी अफ़ीम की चाशनी में डूबकर विश्व गुरु बनने के सपने लेते रहें परन्तु हक़ीक़त में तो यही है कि विश्व गुरु भारत में इंसानी जान की क़ीमत ? (लेखिका - निर्मल रानी /ईएमएस)

शब्द पहेली - 8202

बाएँ से दाएँ
1. लालसा, मांग-3
3. मोटरगाड़ी-4
6. दरवाजे पर दी गई थाप-3
7. मां की माता-2
8. पार्थिव देह-2
10. संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, माधुरी की फिल्म-5
12. स्वदेश, जन्मभूमि-3
15. पाबंदी, रोक-3
17. आश्चर्यचकित होना-5
20. नासिका-2
22. आनेवाला दिन-2
23. समतल-3
24. शमशीर, कृपाण-4
25. फिजूल, व्यर्थ-3

ऊपर से नीचे
2. दुर्जन, बेइमान-5
3. जिसके सिर पर बल न हो, गंजा-3
4. साहूकार, व्यापारी-4
5. जांच, परीक्षण-3
7. मां के पिता-2
9. लाश-2
11. तरुणी, किशोरी-3
13. कार्यविधि-3
14. बेइज्जत होना-2-3
15. हाथी साधने वाला-4
16. मेहंदी-2
18. ताकत, जोर-2
19. अभिनेत्री-3
21. कमी-3

शब्द पहेली -8201 का हल

Jagrutidaur.com, Bangalore

खेल - समाचार

दक्षिण अफ्रीका-श्रीलंका टेस्ट के पहले दिन का खेल बारिश से धुला

डरबन (ईएमएस)। दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच यहां पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल बारिश के कारण नहीं हो पाया। इस मुकाबले में पहले सत्र में ही तेज बारिश आ गयी।इस कारण समय से पहले लंच-ब्रेक लेना पड़ा। इसके बाद बारिश नहीं रुकी जिससे खेल दोबारा शुरू नहीं हो पाया और अंत में दिनभर का खेल समाप्त घोषित करना पड़ा। पहले दिन का खेल समाप्त होने पर दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट पर 80 रन था। मेजबान कप्तान तेम्बा बवूमा 28 रन बनाकर खेल रहे थे। वहीं काइल वेरेन 9 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। वहीं सलामी बल्लेबाज एडेन मार्करम 9 और टोनी डी जॉर्जी 4 रन बनाकर आउट हुए जबकि ट्रिस्टन स्टब्स 16 और डेविड बेडिंघम 4 रन बनाकर पैवेलियन लौटे। दक्षिण अफ्रीका के चार बल्लेबाजों में से 2 बल्लेबाजों को लाहिरु कुमार ने आउट किया। वहीं विश्वा फर्नांडो और असिथ फर्नांडो को एक-एक विकेट मिला।

आईपीएल नीलामी के बाद जमकर चला श्रेयस का बल्ला

हैदराबाद (ईएमएस)। आईपीएल नीलामी के बाद श्रेयस अय्यर का बल्ला जमकर चलता नजर आया। मुम्बई की कप्तानी कर रहे श्रेयस ने शानदार अर्धशतक लगाया जिससे मुम्बई टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ग्रुप-सी के मैच में महाराष्ट्र को पांच विकेट से हरा दिया। श्रेयस ने 39 गेंद में आठ चौकों और तीन छक्कों की सहायता से 71 रन बनाए। वहीं रहाणे ने 34 गेंद में 52 रन बनाये। इसके बाद मुंबई ने जीत के लिए 172 रन का लक्ष्य 17.1 ओवर में हासिल कर लिया। वहीं इससे पहले गेंदबाजी करते हुए शार्दुल ठाकुर और मोहित अवस्थी ने दो दो विकेट लिए जिससे महाराष्ट्र की टीम 9 विकेट पर 171 रन ही बना सकी।

आईपीएल की मेगा नीलामी में पंजाब किंग्स ने श्रेयस को 26 करोड़ 75 लाख रुपये में खरीदे था। इसका प्रभाव उनकी बल्लेबाजी पर भी दिखा। वहीं पंजाब किंग्स की सह मालकिन प्रीति जिंटा भी इस पारी को देखकर बेहद खुश नजर आयीं। अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से श्रेयस ने महाराष्ट्र के गेंदबाजों को कोई अवसर नहीं दिया। आईपीएल नीलामी के बाद ये श्रेयस का पहला मैच था जिसमें वह पूरी लय में दिखे। अब पंजाब की को-ओनर प्रीति जिंटा उनके प्रदर्शन से खुश होंगी।

पाक टीम को भी आने वाले समय में भारत नहीं भेजेंगे : नकवी

लाहौर (ईएमएस)। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने कहा कि जिस प्रकार भारतीय बोर्ड (बीसीसीआई) ने चैम्पयंस ट्रॉफी के लिए टीम भेजने से इंकार किया है। उसको देखते हुए भविष्य में पाक टीम भी भारत का दौरा नहीं कर पायेगी।

नकवी ने गद्दाफी स्टेडियम में निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के बाद कहा, 'यह संभव ही नहीं है कि हम भारत में जाकर सभी टूर्नामेंट खेलें और भारतीय अधिकारी अपनी टीम भेजने को तैयार नहीं हों। हम ऐसी विषम स्थिति नहीं होने दे सकते। नकवी का रुख हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 'हाइब्रिड मॉडल को लेकर नरम दिखा। उन्होंने इससे पहले उन्होंने कहा था कि पीसीबी इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा, 'मैं केवल इतना आश्वासन दे सकता हूं कि बैठक में जो भी होगा, हम अच्छी खबर और फैसले लेकर आएंगे, जिसे हमारे लोग स्वीकार करेंगे।

नकवी ने उम्मीद जताई कि पांच दिसंबर को आईसीसी के चेयरमैन का पद संभालने वाले जय शाह विश्व क्रिकेट और सभी सदस्य बोर्डों के हित में निर्णय लेंगे।

आईसीसी बोर्ड की बैठक आज, चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए 'हाइब्रिड मॉडल पर होगी बात

दुबई (ईएमएस)। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) बोर्ड की शुक्रवार को अहम बैठक होने वाली है। इसमें अगले साल पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के कार्यक्रम और उसे 'हाइब्रिड मॉडल पर आयोजित करने को लेकर फैसला होगा। चैम्पियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने कहा है कि वह सुरक्षा कारणों से अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजेगा। वहीं पाक क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) हाइब्रिड मॉडल पर तैयार नहीं है। आईसीसी बोर्ड की बैठक वर्चुअल तरीके से होगी और इसमें चैंपियंस ट्रॉफी के कार्यक्रम को लेकर कोई हल निकलने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस समय 'हाइब्रिड मॉडल सबसे अच्छा विकल्प है।

आईसीसी के सदस्य पीसीबी को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच के बिना चैंपियंस ट्रॉफी की चमक फीकी पड़ जाएगी और सबसे अहम बात यह है कि इससे बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान होगा। टूर्नामेंट के प्रसारक भी कार्यक्रम में हो रही देरी पर नाराज हैं।

आईसीसी और प्रसारणकर्ता के बीच हुए अनुबंध के अनुसार संचालन संस्था से अपेक्षा की गई थी कि वह टूर्नामेंट का कार्यक्रम कम से कम 90 दिन पहले दे, लेकिन यह समय सीमा पहले ही पार कर ली गई है। भारत ने 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद से पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। आईसीसी ने भी कई बार कहा है कि वह वह किसी भी सदस्य बोर्ड से सरकार की सलाह के विरुद्ध जाने की अपेक्षा नहीं करता है।

पाकिस्तान में अभी जो हालात है उससे भी पीसीबी की दावेदारी कमजोर हुई है। इस्लामाबाद में बड़े पैमाने पर राजनीतिक विरोध के कारण कुछ दिन पहले श्रीलंका ए टीम का पाकिस्तान दौरा बीच में ही रोकना पड़ा था।

आईएलटी 20 क्रिकेट लीग 11 जनवरी से शुरु होगा

दुबई (ईएमएस)। आईएलटी 20 क्रिकेट लीग के तीसरे सत्र का कार्याक्रम घोषित कर दिया गया है। इसमें पहला मुकाबला गत चैंपियन एमआई अमीरात और दुबई कैपिटल्स के बीच 11 जनवरी को होगा। इस टूर्नामेंट में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पंद्रह मैच खेले जाएंगे जबकि अबू धाबी में 11 मैच होंगे। शेष आठ मैचों का आयोजन प्रतिष्ठित शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में किया जाएगा। एक महीने तक चलने वाले टूर्नामेंट में कुल 34 मैच खेले जाएंगे। इसका फाइनल 9 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा।

आईएलटी20 में छह फ्रेंचाइजी टीम एमआई अमीरात, दुबई कैपिटल्स, अबू धाबी नाइट राइडर्स, डेजर्ट वाइपर, गल्फ जाइंट्स और शारजाह वारियर्स भाग लेंगी। आंद्रे रसेल, सुनील नारायण (अबू धाबी नाइट राइडर्स), डेविड वार्नर, निकोलस पूरन, जेसन रॉय, लॉकी फर्ग्यूसन जैसे विश्व के शीर्ष क्रिकेटर इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे।

मीराबाई विश्व चैंपियनशिप से बाहर रहेगी, ज्ञानेश्वरी करेंगी भारतीय दल का नेतृत्व

नई दिल्ली (ईएमएस)। मीराबाई चानू अगले सप्ताह 6 दिसंबसर से बहरीन के मनामा में होने वाली भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में भाग नहीं लेंगी। चानू ने कहा है कि उन्होंने ये फैसला अपना 'रिहैबिलिटेशन जारी रखने के लिए लिया है। चानू ने अगस्त में पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 49 किग्रा श्रेणी में चौथे स्थान पर रहने के बाद से किसी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया है। मुख्य राष्ट्रीय कोच विजय शर्मा ने कहा, 'पेरिस ओलंपिक के बाद से ही मीरा अभी भी रिहैबिलिटेशन में हैं। वह इस विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लेगी।कोच के अनुसार चानू के नहीं रहने से राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव छह दिसंबर से शुरू होने वाली विश्व चैम्पियनशिप में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगी।

पिछले साल एशियाई खेलों में चोट लगने के बाद से ही मीराबाई की फिटनेस को लेकर पेरिस ओलंपिक के दौरान भी चर्चा होती रही। एशियाई खेलों में पदक जीतने का उनका सपना पिछले साल टूट गया था क्योंकि वह सिर्फ यही ट्रॉफी नहीं जीत पाई हैं। कोच ने कहा, ' चानू के लिए स्वस्थ होना अहम है क्योंकि हमें 2026 राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों की तैयारी शुरू करनी होगी।

चानू के नहीं रहने से राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव छह दिसंबर से शुरू होने वाली विश्व चैम्पियनशिप में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगी। ज्ञानेश्वरी 49 किलो वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। वहीं राष्ट्रमंडल खेलों की रजत पदक विजेता बिंदियारानी देवी 55 किग्रा और राष्ट्रीय चैम्पियनशिप और खेलो इंडिया भारोत्तोलन लीग की स्वर्ण विजेता दितिमोनी सोनोवाल 64 किग्रा अन्य दो भारतीय भारोत्तोलक हैं जो विश्व प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी।

महिला टीम : ज्ञानेश्वरी यादव (49 किग्रा), बिंदिरानी देवी (55 किग्रा), दितिमोनी सोनोवाल (64 किग्रा)।

रोनाल्डो, मेसी के 100 गोल वाले क्लब में शामिल हुए लेवांडोव्स्की

रोम (ईएमएस)। पोलैंड के पेशेवर फुटबॉलर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की चैंपियंस लीग फुटबाल टूर्नामेंट में 100 गोल करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले ये उपलब्धि केवल पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के नाम थी।

लेवांडोव्स्की ने ब्रेस्ट के खिलाफ बार्सिलोना की 3-0 से जीत के दौरान ही चैंपियंस लीग में अपने 100वां गोल पूरे किये। इस स्टार स्ट्राइकर ने दूसरे हाफ के इंजरी टाइम में प्रतियोगिता में अपना 101वां गोल दागा। चैंपियंस लीग में सबसे अधिक 140 गोल रोनाल्डो के नाम हैं जबकि मेसी के नाम 129 गोल दर्ज हैं। लेवांडोव्स्की ने 100 गोल करने पर कहा, 'यह बहुत अच्छी संख्या है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं चैंपियंस लीग में इतने गोल कर पाऊंगा। मैं क्रिस्टियानो और मेसी के क्लब में शामिल होकर उत्साहित हूं। लेवांडोव्स्की चैंपियंस लीग में अपने 125वें मैच में यहां तक पहुंचे हैं। वहीं मेसी ने 123 और रोनाल्डो ने 137 मैच में यह उपलब्धि हासिल की थी। बार्सिलोना की टीम इस जीत के साथ ही लीग में दूसरे नंबर पर पहुंच गयी है।

शेयर बाजार टूटा , सेंसेक्स 1,190 अंक नीचे आया

निफ्टी 360 गिरा

मुम्बई (ईएमएस)। भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को भारी गिरावट दर्ज की गयी। बाजार में ये गिरावट दुनिया भर से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही बिकवाली हावी रहने से आई है। इसके अलावा मासिक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (एफएंडओ) एक्सपायरी के दबाव में भी बाजार टूटा है। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 1,190 अंक करीब 1.48फीसदी टूटकर 79,043.74 पर बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान सेंसेक्स 80,447.40 के उच्च और 78,918.92 के निचले स्तर तक पहुंचा। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 50 भी 360.75 अंक तकरीबन 1.49 फीसदी नीचे आकर 23,914.15 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान निफ्टी 24,345.75 के उच्च और 23,873.35 के निचले स्तर पर पहुंचा।

जानकारों के अनुसार बाजार में आई गिरावट का एक प्रमुख कारण रूस के यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के कारण बढ़े तनाव और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक्सपायरी से जुड़ी बिकवाली को बताया है।

आज कारोबार के दौरान निफ्टी के 46 शेयर गिरावट पर बंद हुए। सबसे ज्यादा नुकसान एसबीआई लाइफ, इंफोसिस, एचडीएफसी लाइफ, महिंद्रा एंड महिंद्रा और अदाणी पोर्ट्स के शेयरों को हुआ। इनमें 5.4 फीसदी तक गिरावट रही। वहीं, अदाणी एंटरप्राइजेज, श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई और सिप्ला जैसे चार शेयर ही 1.63 फीसदी ऊपर आये।

कारोबार के दौरान निफ्टी मिडकैप 100 और निफ्टी स्मॉलकैप100 इंडेक्स 0.05 फीसदी की हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं आईटी सेक्टर पर सबसे ज्यादा दबाव रहा। निफ्टी आईटी इंडेक्स 2 फीसदी से ज्यादा नीचे आया जबकि निफ्टी ऑटो, फाइनेंशियल्स, प्राइवेट बैंक, कंज्यूमर डयूरेबल्स और हेल्थकेयर इंडेक्स में भी गिरावट रही। वहीं निफ्टी पीएसयू बैंक और मीडिया इंडेक्स में बढ़त आई।

इससे पहले आज सुबह कारोबारी सत्र की शुरुआत में हल्की बढ़त देखी जा रही है। बीएसई सेंसेक्स 50 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 80,282 पर खुला, जबकि एनएसई निफ्टी 50 शुरुआती कारोबार में 20 अंकों की बढ़त के साथ 24,296 पर कारोबार करता दिखा। विदेशी बाजारों की बात करें तो दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स शुरुआत में थोड़ा गिरा, लेकिन बाद में 0.15 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुआ। जापान का निक्केई 0.30 फीसदी गिरा, जबकि ऑस्ट्रेलिया का एएसएक्स 200 बढ़त के साथ खुला और 0.43 फीसदी ऊपर बंद हुआ। वॉल स्ट्रीट पर हल्का कारोबार हुआ और ज्यादातर इंडेक्स नुकसान में रहे। नैस्डैक 0.6 फीसदी गिरा, जबकि डाओ जोन्स शुरुआती बढ़त गंवाकर 0.31 फीसदी नीचे बंद हुआ।

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट

- सोना 75,450 रुपए प्र?ति 10 ग्राम, चांदी 86,900 रुपए के करीब

नई दिल्ली (ईएमएस)। सोने-चांदी के वायदा भाव में गुरुवार को ?गिरावट देखी जा रही है। गुरुवार को दोनों के वायदा भाव गिरावट के साथ खुले। सोने के वायदा भाव 75,450 रुपये के करीब, जबकि चांदी के वायदा भाव 86,900 रुपये के करीब कारोबार कर रहे थे। वै?श्विक बाजार में सोने-चांदी की वायदा कीमतें भी कमजोर ?दिखाई दे रही है। सोने के वायदा भाव की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का बेंचमार्क दिसंबर कॉन्ट्रेक्ट 259 रुपये की गिरावट के साथ 75,501 रुपये के भाव पर खुला। इस समय यह 315 रुपये की गिरावट के साथ 75,445 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। चांदी के वायदा भाव की शुरुआत भी सुस्त रही। एमसीएक्स पर चांदी का बेंचमार्क दिसंबर कॉन्ट्रेक्ट 681 रुपये की गिरावट के साथ 86,999 रुपये पर खुला। इस समय यह 777 रुपये की नरमी के साथ 86,903 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। वै?श्विक बाजार में आज सोने-चांदी के वायदा भाव में नरमी देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर सोना 2,636.39 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला। पिछला बंद भाव 2,639.90 डॉलर प्रति औंस था। इस समय यह 11.20 डॉलर की गिरावट के साथ 2,628.70 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था। कॉमेक्स पर चांदी के वायदा भाव 30.13 डॉलर के भाव पर खुले, पिछला बंद भाव 30.11 डॉलर था। हालांकि इसके भाव बाद में खबर लिखे जाने के समय यह 0.31 डॉलर की नरमी के साथ 29.80 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था।

बुशरा बीबी को लेकर इमरान खान की पार्टी में बवाल

इस्लामाबाद (ईएमएस)। इस्लामाबाद में तीन दिन तक चले प्रदर्शन के बाद इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने आंदोलन खत्म कर दिया है। इस उग्र प्रदर्शन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कई कार्यकर्ता मारे गए हैं, जबकि छह सुरक्षाकर्मी भी मारे गए। इस बीच पीटीआई में पार्टी के मुखिया इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

कई नेताओं ने यह सवाल उठाया है कि आखिर कैसे बुशरा बीबी ने आंदोलन को लेकर फैसला लिया और इस्लामाबाद के डी-चौक का घेराव करने की बात तय हुई। सवाल उठाए जा रहे हैं कि बुशरा बीबी किस अधिकार से यह फैसले ले रही हैं। खासतौर पर सुरक्षा बलों की फायरिंग में पार्टी कार्यकर्ताओं के मारे जाने से गुस्सा भड़क गया है। बुधवार को पीटीआई की आंतरिक कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें नेताओं ने बुशरा बीबी के रोल पर चर्चा की। कमेटी की मीटिंग में पीटीआई कार्यकर्ताओं के मारे जाने की निंदा की गई। इसके अलावा न्यायिक जांच कराने की मांग भी की गई। यही नहीं इस बात पर भी चर्चा हुई कि आखिल किसके आदेश पर इस्लामाबाद के डी-चौक का घेराव करने का फैसला हुआ था। बुशरा बीबी पर आरोप लग रहे हैं कि वह बिना किसी अधिकार के ही पार्टी को लेकर जरूरी फैसले ले रहे हैं। पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी की बैठक में बुशरा बीबी पर खूब सवाल उठे, लेकिन किसी ने भी उनका बचाव नहीं किया।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना अब देश के कुल 788 जिलों में से 687 जिलों में लागू हो चुकी

नई दिल्ली (ईएमएस) । कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना अब देश के कुल 788 जिलों में से 687 जिलों में लागू हो चुकी है। वर्ष 2014 में यह 393 जिलों में ही लागू थी लेकिन पिछले 10 वर्षों में इस प्रक्रिया में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ सहयोग करके ऐंघ्य योजना को अब शेष 101 जिलों में भी विस्तारित किया जाएगा।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया के मार्गदर्शन में काम करते हुए ईएसआईसी आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) की सुविधाओं के साथ कर्मचारियों और उनके आश्रितों तक स्वास्थ्य सेवा की पहुंच बढ़ाने पर काम कर रहा है। श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य लाभ और चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना सरकार की प्राथमिकता है। इससे अधिक उत्पादक श्रम शक्ति का विकास होगा, जिससे 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण को गति मिलेगी। इस पहल से 114.434.43 करोड़ से अधिक ईएसआईसी लाभार्थियों और उनके परिवारों को पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण और व्यापक चिकित्सा देखभाल का लाभ मिलेगा। इस संदर्भ में केंद्र सरकार की श्रम एवं रोजगार सचिव सुमिता डावरा ने हाल ही में इन दोनों योजनाओं के विस्तार और कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा भी की।

ईएसआईसी के महानिदेशक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि इस विस्तार के माध्यम से ईएसआईसी लाभार्थी देश भर में 30,000 से अधिक आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से सूचीबद्ध अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे, जिसमें उपचार लागत पर कोई वित्तीय सीमा नहीं होगी। यह भागीदारी न केवल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को बढ़ाएगी बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगी कि उपचार व्यय पूरी तरह से कवर हो, जिससे सभी लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य सेवा आसानी से सुलभ और सस्ती हो सके। देश भर के धर्मार्थ अस्पतालों को भी ईएसआई लाभार्थियों के उपचार के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

ईएसआई योजना के अंतर्गत मौजूदा चिकित्सा देखभाल 165 अस्पतालों, 1590 डिस्पेंसरियों, 105 डिस्पेंसरी सह शाखा कार्यालयों (डीसीबीओ) और लगभग 2900 सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपलब्ध है।

लैंडस्केप फायर्स जनित वायु प्रदूषण से होती है हर साल 15 लाख मौतें

नई दिल्ली (ईएमएस) । ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में किए गए एक अंतरराष्ट्रीय शोध में यह बात सामने आई है कि हर साल दुनिया भर में 15 लाख से अधिक मौतें लैंडस्केप फायर्स (जंगल, घास के मैदान, और अन्य प्रकार के खुले क्षेत्रों में लगने वाली आग) की वजह से होने वाले वायु प्रदूषण से होती है। मेलबर्न में मोनाश विश्वविद्यालय द्वारा किए गए शोध के अनुसार 2000 से 2019 के बीच प्रति वर्ष 15 लाख 30 हजार मौतें जंगल की आग से होने वाले वायु प्रदूषण के कारण हुईं। अध्ययन में पाया गया कि भूदृश्य आग (लैंडस्केप फायर्स) से होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होने वाली सभी मौतों में से 90 प्रतिशत से अधिक मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में हुईं, जिसमें विशेष रूप से सब-सहारा अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व, दक्षिण और पूर्वी एशिया शामिल है।

लैंडस्केप फायर्स से होने वाले वायु प्रदूषण का सेहत पर पड़ने वाले असर को लेकर अध्ययन किया गया। जिसमें दुनिया भर के कई विश्वविद्यालयों से आए शोधकर्ताओं ने हिस्सा लिया। विश्व स्तर पर होने वाली 15 लाख 30 हजार वार्षिक मौतों में से 450,000 हृदय रोग और 220,000 श्वसन रोग के कारण हुईं। जंगल की आग से निकलने वाले महीन कणों के कारण 77.6 प्रतिशत और सतही ओजोन के कारण 22.4 प्रतिशत मौत हुई।

लेखकों ने शोध में कहा, ''जलवायु परिवर्तन के कारण जंगल में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और गंभीर होती जा रही हैं, इसलिए जलवायु से संबंधित मृत्यु दर और उससे जुड़े पर्यावरणीय गंभीर प्रभाव को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।'' जिन देशों में भूदृश्य आग के कारण मृत्यु दर सबसे अधिक है, वे सभी सब-सहारा अफ्रीका में हैं।

लेखक उच्च आय वाले देशों से वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने की वकालत करते हैं, ताकि कमजोर विकासशील देशों को जंगल की आग से उत्पन्न वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभावों का प्रबंधन करने और मृत्यु दर में सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने में मदद मिल सके।

खैबर पख्तूनख्वा में भी हालत नाजुक, अमेरिका ने जारी की एडवायजरी

नागरिकों से कहा तुरंत छोड़ें इलाका, खैबर, पेशावर गोल्फ क्लब जाने से बचें

वाशिंगटन,(ईएमएस)। पाकिस्तान में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार चरम पर है। बीते दिनों पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस्लामाबाद में पैदल मार्च निकाला था। उधर, खैबर पख्तूनख्वा में भी हालत नाजुक है। वहां पिछले दिनों आतंकी हमला हुआ था। इसके बाद अब अमेरिका ने अपने नागरिकों को खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में जाने से रोक दिया है।

अमेरिका ने एडवायजरी जारी कर कहा है कि उसके नागरिक खैबर, पेशावर गोल्फ क्लब, खैबर रोड, होटल सेरेना समेत अनेक इलाकों में 16 दिसंबर तक न जाएं। अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों से कहा है कि 16 दिसंबर 2024 की अवधि के दौरान इस इलाके और आसपास के क्षेत्रों में जाने से बचें और अपनी यात्रा की योजनाओं पर फिर से पुनर्विचार करें। अमेरिकी ने अपने नागरिकों से कहा है कि वह आतंकवाद के कारण इस इलाके में यात्रा न करें। इसलिए, सलाह जारी की गई है उस सलाह को ध्यान में रखें। यदि आप किसी कारणवश इन इलाकों में मौजूद हैं तो तत्काल वह इलाका छोड़ दें। अमेरिकी द्वारा जारी इस अलर्ट के बाद माना जा रहा है कि पाकिस्तान में कोई बड़ा आतंकवादी हमला इस अवधि में हो सकता है।

दक्षिण कोरिया के केंद्रीय बैंक ने लगातार दूसरे महीने नी?तिगत दर घटाई

- बैंक ने आगामी वर्षों के लिए भी अर्थव्यवस्था की पुनरावृत्ति में गिरावट का अनुमान लगाया

सियोल (ईएमएस)। दक्षिण कोरिया के केंद्रीय बैंक ने नवंबर माह में अपनी प्रमुख नीति दर में कटौती की घोषित करते हुए अर्थव्यवस्था के मुक्काम विकास की उम्मीद दर को घटाने की घोषणा की। बैंक ऑफ कोरिया ने दूसरे महीने भी बारीकी से नीतिगत ब्याज दर में चौथाई प्रतिशत की कटौती की और उसे तीन प्रतिशत किया। इस साल के पूर्वानुमानों को कम करते हुए बैंक ने आगामी वर्षों के लिए भी अर्थव्यवस्था की पुनरावृत्ति में गिरावट का अनुमान लगाया। बैंक ने अपने उद्योग के नजरिए से अधिक उधार लेने की लागत में कमी और मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस कदम की चेतावनी जारी की। उच्च मुद्रास्फीति और अधिक घरेलू ऋण के परिणाम स्थिति में जोखिम उलझा हुआ है, जो अर्थव्यवस्था को एक नया धक्का पहुंचा सकता है। इस पहल के हिसाब से बैंक ने अक्टूबर में भी नीतिगत ब्याज दरों में कटौती की थी, परन्तु अब भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बाजार गतिविधियों में वैशिष्टय, उद्योग व्यापार संघर्ष और निर्यात के मामले में कोहराम बना रहेगा, जिससे अर्थव्यवस्था के विकास में धीमापन की संभावना है। बैंक ने वही उम्मीद जताई कि भविष्य में घरेलू खपत में वृद्धि हो सकती है, लेकिन विशेष रूप से न केवल निर्यात में, बल्कि प्रमुख उद्योगों में भी प्रतिस्पर्धा और व्यापार नीतियों की मजबूती की आवश्यकता है।

एचटीएस विद्रोही समूह ने सीरियाई सैन्य ठिकानों पर किया हमला, 89 लोगों की मौत

दमिश्क (ईएमएस)। हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) विद्रोही समूह और उसके सहयोगी गुटों ने अलेप्पो प्रांत के ग्रामीण इलाकों में सीरियाई सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला किया। इन झड़पों में 89 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एचटीएस और उसके समर्थक गुटों के 52 लड़ाके और सीरियाई सरकारी बलों के 37 सैनिक शामिल थे।

रिपोर्ट में सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के हवाले से बताया गया कि एचटीएस और अल-फतह अल-मुबीन ऑपरेशन रूम के गुटों ने ऑपरेशन शुरू होने के 12 घंटे से भी कम समय में 21 गांवों, कस्बों और रणनीतिक स्थलों पर नियंत्रण कर लिया।

पांच सीरियाई सैनिकों को एचटीएस ने बंधक बनाया और हथियार डिपो, बख्तरबंद वाहन और भारी हथियार भी जब्त कर लिए। ऑब्जर्वेटरी ने बताया कि हमले के जवाब में, रूसी युद्धक विमानों ने अटारीब शहर के आसपास विद्रोहियों गुटों के ठिकानों पर वैक्यूम मिसाइलों का उपयोग करके हमले किए। सीरियाई सरकारी बलों ने अटारीब, दारत इज्जा और आसपास के गांवों पर सैकड़ों तोपों और रॉकेटों से बमबारी की। एक दिन पहले, एचटीएस की तैयारियों कारण पश्चिमी अलेप्पो के ग्रामीण इलाकों में अतारिब और आसपास के गांवों से नागरिकों को बड़ी संख्या में पलायन करना पड़ा था। एचटीएस, जिसे पहले नुसरा फ्रंट के नाम से जाना जाता था, को कई देश आतंकवादी संगठन मानते हैं।

रूस ने यूक्रेन पर 188 मिसाइलें-ड्रोन दागे

एनर्जी ठिकानों को निशाना बनाया, 10 लाख लोग बिना बिजली 0 डिग्री तापमान में रहने को मजबूर

कीव (ईएमएस)। रूस ने 188 मिसाइल्स और ड्रोन से यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री ने बताया, हमले की वजह से देश में ऊर्जा के लगभग सारे साधन ठप पड़ गए हैं। यूक्रेन में लगभग 10 लाख लोगों को 0 डिग्री तापमान में बिना बिजली के रात गुजारनी पड़ी। हालांकि, अभी तक रूस ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया।

यूक्रेनी ऊर्जा मंत्री हरमन हालुशेंको का कहना है कि, यूक्रेन में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो रहे हैं, इस वजह से नेशनल पावर ग्रिड के ऑपरेटर ने इमरजेंसी बिजली कटौती शुरू कर दी है। कीव, ओडेसा, निप्रो और डोनेट्स्क में बिजली सप्लाई में मुश्किल हो रही है। रूस ने फरवरी 2022 के बाद से कई बार यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है। इस वजह से बार-बार देश में इमरजेंसी बिजली कटौती और रोलिंग ब्लैकआउट की स्थिति पैदा हुई है।

राजधानी कीव पर ड्रोन के बाद मिसाइल अटैक

रूस की तरफ से यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी हवाई हमले जारी हैं। खास बात यह है कि रूस अब ड्रोन की जगह मिसाइल से अटैक कर रहा है। यूक्रेनी मिलिट्री का कहना है कि कीव में रूस के सभी मिसाइल और ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया गया। हालांकि, कुछ मीडिया आउटलेट्स का कहना है कि कीव के लोगों को लगभग हर रात ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ रहा है। कीव में अभी भी इमरजेंसी बिजली कटौती चल रही है।

रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल दागी

33 महीनों से जारी जंग के बीच कुछ दिन पहले ही रूस ने पहली बार यूक्रेन के निप्रो शहर पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। वहीं, यूक्रेन ने रूस पर पश्चिमी देशों से मिले खतरनाक हथियार दागे हैं। ब्रिटेन ने हाल ही में यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइलों की नई खेप भेजी है। स्टॉर्म शैडो की रेंज 250 किमी से ज्यादा है। इसका इस्तेमाल 2000 के दशक की शुरुआत से किया जा रहा है। इसके जवाब में रूस ने यूक्रेन पर मध्यम दूरी की नई हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक दागी थी। यूक्रेनी नेवी का कहना है कि रूस की नौ सेना ने ब्लैक सी में कॉम्बैट डयूटी के लिए चार कैलिबर कैरियर शिप को तैनात किया है, जिनमें 22 मिसाइल्स हैं।

वित्त वर्ष 2024 में सेकंड हैंड कार रिटेलर कार्स 24 को 498 करोड़ का हुआ नुकसान

नई दिल्ली,(ईएमएस)। ऑनलाइन सेकंड हैंड कार रिटेलर प्लेटफॉर्म कार्स24 का नुकसान वित्त वर्ष 2024 में 6.4 बढ़कर 498 करोड़ रुपए हो गया है। वित्त वर्ष 2023 में यह 468 करोड़ रुपए था। कंपनी के खर्च में वित्त वर्ष 2024 में बढ़ोतरी देखने को मिली है और यह सालाना आधार पर 23.3 फीसदी बढ़कर 7,461 करोड़ रुपए हो गया है, जो वित्त वर्ष 2023 में 6,053 करोड़ रुपए था।

वित्त वर्ष 2024 में कार्स24 की ओर से सबसे ज्यादा 6,106 करोड़ रुपए गाड़ियां खरीदने पर खर्च किए गए हैं। इसमें सालाना आधार पर 23.8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है और यह कुल लागत का 81.8 फीसदी है। इसके अलावा बाकी राशि एंम्पलॉय बेनिफिट, विज्ञापन, लीगल, ब्रोकर्स को कमीशन और अन्य मदों पर खर्च किए गए हैं। पिछले वित्त वर्ष में कंपनी की आय में भी इजाफा हुआ है और यह 25.1 फीसदी बढ़कर 6,917 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि वित्त वर्ष 2023 में 5,530 करोड़ रुपए थी। कार्स24 की आय का मुख्य जरिया कारों की बिक्री है। इसका आय में योगदान 92 फीसदी है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 में कार की बिक्री से आय 24 फीसदी बढ़कर 6,400 करोड़ रुपए रही, जो कि वित्त वर्ष 2023 में 5,164 करोड़ रुपए थी। बाकी की आय फाइनेंसियल सर्विसेज, सर्विस फीस, पार्किंग फीस और अन्य सेवाएं जैसे इंश्योरेंस और वारंटी जैसे घटकों से हुई है। कंपनी के मुताबिक उसने वित्त वर्ष 2024 में 2,00,000 से ज्यादा कारों की बिक्री की।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कार्स24 की ओर से बीते तीन सालों में कोई नई फंडिंग नहीं जुटाई गई है। दिसंबर 2021 में कंपनी ने 3.3 बिलियन डॉलर के मूल्यांकन पर 450 मिलियन डॉलर जुटाए। इसके प्रमुख निवेशकों में अल्फा वेव, सॉफ्टबैंक, टेनसेंट और डीएसटी ग्लोबल शामिल हैं। कार्स24 की स्थापना 2015 में हुई थी। कंपनी गाड़ियों की खरीदारी, बिक्री, लोन, बीमा, ड्राइवर ऑन डिमांड, फास्टैग, चालान, स्क्रैपिंग और अन्य सेवाएं प्रदान करने का काम करती है।

सीरिया में विद्रोही गुट का मिलिट्री बेस पर कब्जा

हथियार और वाहन छीने, 89 लोगों की मौत; अलकायदा के फिर हावी होने का डर

दमिश्क(ईएमएस)। सीरिया में विद्रोही गुटों के हमले में बुधवार को 89 लोग मारे गए। ये पिछले 4 साल में विद्रोहियों की तरफ से किया गया सबसे बड़ा हमला था। उन्होंने सीरियाई आर्मी के एक मिलिट्री बेस पर भी कब्जा कर लिया है। जिन गुटों ने बुधवार को हमला किया उनमें से एक संगठन हयात तहरीर अल-शम को अल कायदा का समर्थन हासिल है।

ये आतंकी संगठन सीरिया के बड़े शहरों में से एक अलेप्पो में साढ़े 9 किलोमीटर तक घुस चुके हैं। इसके लड़ाकों ने बशर अल असद की सरकार के समर्थन वाली सेना के हथियारों और वाहनों पर कब्जा कर लिया है। 46 मिलिट्री बेस पर कब्जे का दावा सीरिया के विद्रोही गुटों ने टेलीग्राम पर दावा किया है कि उन्होंने सीरियाई सरकार के 46 सैन्य अड्डों को कब्जे में ले लिया है। वे सिर्फ 10 घंटों के भीतर अलेप्पो शहर के कई गांव पर कब्जा करने में कामयाब रहे हैं। हालांकि सीरियाई सरकार ने इन दावों पर कोई कुछ नहीं कहा है। 2020 में तुर्किये की मदद से विद्रोहियों और असद सरकार के बीच एक समझौता कराया गया था, जिससे वहां बड़े हमलों में कमी आई थी।

सीरिया में 2011 में शुरू हुआ गृहयुद्ध

2011 में अरब क्रांति के साथ ही सीरिया में गृहयुद्ध की शुरुआत हुई थी। साल 2000 से सीरिया के सत्ता में काबिज बशर अल असद की तानाशाही सरकार के खिलाफ लोकतंत्र समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। इसके बाद एक फ्री सीरियन आर्मी के नाम से एक विद्रोही गुट तैयार हुआ। विद्रोही गुट के बनने के साथ ही सीरिया में गृहयुद्ध की शुरुआत हो गई थी। इसमें अमेरिका, रूस, ईरान और सीरिया के शामिल होने के बाद ये संघर्ष और बढ़ता गया। इस बीच यहां आतंकवादी संगठन ढ्ढस्ढ्ढस् ने भी अपने पैर पसार लिए थे। 2020 के सीजफायर समझौते के बाद यहां सिर्फ छुटपुट झड़प ही हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक एक दशक तक चले गृहयुद्ध में 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके अलावा लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा था।

तनाव दूर करने 1,000 घरों में की सेंधमारी, आरोपी गिरफ्तार

- बहुत टेंशन में था युवक, तनाव दूर करने के ?लिए खोजा था अनोखा उपाय

टोक्यो (ईएमएस)। जापान में एक अजीब घटना सामने आई है जिसके तहत एक आदमी ने तनाव से निपटने के लिए 1,000 घरों में सेंधमारी की है। जापानी पुलिस ने 37 वर्षीय इस शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने एक अजीब तरीके से तनाव से निपटने की कोशिश की है। उसने बताया कि उसे दूसरों के घरों में घुसना पसंद है और उसने 1,000 से अधिक बार ऐसा किया है। आरोपी ने पुलिस के सामने यह बताया कि उसे इस कार्रवाई से रोमांच मिलता है और इससे उसका स्ट्रेस कम हो जाता है। वह समय-समय पर दक्षिणी जापान के घरों में घुस जाता था, जिससे उसे ऊब व तनाव से बचने का लगता था। कोई भी व्यक्ति तनाव या चिंता से गुजर रहा है, तो वह इस तरह की गैरकानूनी कार्रवाई से दूर रहने की सलाह दी जाती है। चोरी जैसे गलत कामों से विचलित होने की बजाय, स्वास्थ्यवर्धक तरीके से तनाव से निपटना चाहिए। एक स्वस्थ मानसिकता खोजने के लिए योग, मेधिटेशन, क्रिएटिव एक्टिविटीज जैसे विभिन्न तकनीकों का सहारा लेना बेहद महत्वपूर्ण है। तनाव से निपटने के लिए गुरु या सलाहकार की सहायता भी प्रभावी साबित हो सकती है। किसी भी समस्या का समाधान गारंटी वाले तरीके से ही करना चाहिए, न कि गर्भावस्था में अस्थायी सुख की तलाश में अनैतिक कृत्यों में धकेलने की कोई सोची-समझी प्रवृत्ति।

दक्षिण कोरिया में 117 साल बाद रिकॉर्ड बर्फबारी, सियोल में जीवन ठप

सियोल (ईएमएस)। दक्षिण कोरिया इन दिनों भीषण बर्फबारी हो रही है, जिसे स्थानीय मीडिया ने सफेद सुनामी करार दिया है। इस दुर्लभ घटना से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सियोल में नवंबर में सबसे भारी बर्फबारी दर्ज की गई है, जो 1907 के बाद का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। राजधानी सियोल में 16 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है, जो पिछले 117 वर्षों का रिकॉर्ड है। इस दुर्लभ बर्फबारी के कारण परिवहन सेवाएं ठप हो गई हैं। कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, सड़कें बंद हैं और ट्रेनों में देरी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार, यह बर्फबारी तेज पश्चिमी हवाओं और तापमान में अचानक बदलाव के कारण हुई है। बर्फबारी के चलते सियोल के आसपास एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने और गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है। प्रशासन और मौसम विभाग ने जनता को सुरक्षित रहने और सरकारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

बोलीविया में ईंधन की कमी की समस्या का सामना कर रहे लोग

- ईंधन की कमी के कारण जीवन और व्यवसाय में बढ़ रही हैं दिक्कतें

एल आल्टो (ईएमएस)। बोलीविया में ईंधन तेजी से सबसे दुर्लभ वस्तुओं में से एक बनता जा रहा है। दक्षिण अमेरिका में प्राकृतिक गैस के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक बोलिविया में पेट्रोल पंपों के बाहर कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। कुछ चालक अब अपने कतारों में खड़े ट्रकों के पास ही खाने-पीने और सोने के लिए जा रहे हैं। इन लोगों की निराशा बढ़ती जा रही है, क्योंकि ईंधन की कमी के कारण जीवन और व्यवसाय में दिक्कतें बढ़ रही हैं। बोलीविया के राष्ट्रपति लुइस आर्से ने सरकार के द्वारा ईंधन की कमी को दूर करने के लिए कई उपाय अपनाए हैं, लेकिन समस्या का हल अभी तक नहीं निकल पाया है। लोगों का कहना है कि सरकार को समस्या को स्वीकार करने के साथ ही इसे हल करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। इस कठिनाई से उबरने के लिए बोलीविया के लोगों ने राजधानी ला पाज़ में मार्च किया और सड़कों पर सब कुछ महंगा है के नारे लगाए। मुद्रा की कमी से सामान की कीमतें भी बढ़ रही हैं, जिससे आम जनता को भी परेशानियां हो रही हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए बोलीविया की सरकार और लोगों के बीच सहयोग और समझौते की आवश्यकता है। बिना सहयोग के यह समस्या हल नहीं हो सकती और लोगों की परेशानियां और बढ़ सकती हैं।

चीन की सेना प्रमुख जनरल झांग योशिया इस्लामाबाद पहुंचे

पाक में चीनी नागरिकों पर आतंकी हमलों से चिंतित

इस्लामाबाद (ईएमएस)। पाकिस्तान में चीनी कर्मचारियों और नागरिकों पर आतंकी हमलों पर चिंतित चीन की सेना के प्रमुख जनरल झांग योशिया इस्लामाबाद पहुंचे। उनके साथ एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी गया है। बता दें कि चीन ने पाकिस्तान से मांग की है कि हम कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए अपनी फोर्स भी भेज सकते हैं। वहीं पाकिस्तान इस पर राजी नहीं है और वह इसे चीन के साथ भरोसे की कमी के तौर पर देख रहा है। जनरल झांग की पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर से बातचीत हुई। पाकिस्तानी सेना की प्रचार यूनिट आईएसपीआर की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि इस वार्ता में क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थिरता और आपसी रक्षा सहयोग बढ़ाने को लेकर बात हुई। पाक सूत्रों का कहना है कि जनरल झांग ने आतंकवाद के खिलाफ चल रहे अभियानों को लेकर बात की। खासतौर पर चीनी नागरिकों पर पाकिस्तान में हमलों को लेकर उन्होंने चिंता जताई और पूछा कि कैसे इन पर लगाम कसी जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन अपने नागरिकों की सुरक्षा को अपने हाथ में लेने की मांग कर रहा है। वहीं पाकिस्तान का कहना है कि सुरक्षा पर चर्चा के साथ ही संप्रभुता पर भी बात की गई। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस बातचीत में अफगानिस्तान और क्षेत्र में भारत की भूमिका को लेकर भी बात हुई। खासतौर पर अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठनों को लेकर भी बातचीत की गई। पाकिस्तान और चीन की सेना का इन दिनों सैन्य अभ्यास भी चल रहा है।

इजराइल और हिजबुल्लाह में सीजफायर, अब गाजा में भी हो सकती है शांति

-हमास और इजराइल के बीच अनाधिकारिक तौर पर जंग अब भी जारी है

गाजा,(ईएमएस)। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बुधवार सुबह सीजफायर हो गया। यूएनएससी रिजॉल्यूशन के तहत इस शांति की खास बात ये है कि सीजफायर सिर्फ 60 दिनों के लिए है। इस मियाद में इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों पक्ष अपनी-अपनी तरफ से शांति की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या ये वक्त खत्म होते ही मिडिल ईस्ट फिर अशांत हो सकता है?

पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने एक हमले में हजारों इजराइली नागरिकों की जान ले ली और ढाई सौ से ज्यादा को अगवा कर लिए थे। इसके बाद इजराइल ने भी हमला किया था और मिडिल ईस्ट में चिंगारी ने आग का रुप ले लिया। इसमें लेबनान का चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह भी शामिल हो गया, जो हमास की विचारधारा को सपोर्ट करता है। हमास और इजराइल के बीच तो अनाधिकारिक तौर पर जंग अब भी जारी है लेकिन हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच दो महीनों का सीजफायर हो चुका है।

युद्धविराम, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के 1701 रिजॉल्यूशन पर आधारित है। यूएनएससी यह प्रस्ताव साल 2006 में लेकर आई थी, जिसका मकसद हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच तनाव को कम करना है। साथ ही ये बफर जोन में स्थाई सीजफायर की बात भी करता है। बता दें कि दक्षिणी हिस्से में ही हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर है। अब इस जगह से दोनों को ही हटने के लिए कहा गया है और लेबनानी सेना वहां रहते हुए ये तय करेगी कि युद्धविराम पूरी तरह से लागू हो सके।

पिछले कुछ दिनों में दोनों के बीच हमलों में कमी आई। यूएनएससी का रिजॉल्यूशन भी एकाएक लागू नहीं हुआ, बल्कि कई बड़े देश इसके लिए काम कर रहे थे। असल में हमलों के बीच लेबनान में हजारों जानें जा चुकीं और विस्थापन भी बढ़ गया था। यही वजह है कि अमेरिका समेत पूरा यूरोप एक्शन में आ गया। इस दौरान हिजबुल्लाह लेबनान और इजरायल के बीच के बफर जोन से अपने लड़ाके हटा लेगा। साथ ही इजरायल भी लेबनानी बॉर्डर से हट जाएगी। इन दोनों की बजाए वहां लेबनानी आर्मी होगी जो तय करेगी कि अंदर-अंदर कोई सुगबुगाहट न हो।

सीजफायर समझौता फिलहाल 60 दिनों के लिए है। इस दौरान साउथ लेबनान के लाखों लोगों समेत उत्तरी लेबनान की भी हजारों की आबादी घर लौट सकेगी। बता दें उत्तरी हिस्से में इजराइल के भी काफी लोग हैं, जो लड़ाई की वजह से होटलों में रह रहे हैं। इसका बड़ा खर्च सरकार उठा रही है, जिससे इजराइल पर आर्थिक दबाव बना है। युद्ध रुकने पर ये भी रुकेगा। वैसे तो मध्यस्थता कर रहे देशों ने इसे परमानेंट पीस की नींव कहा है लेकिन मिडिल ईस्ट के इतिहास को देखते हुए कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता

अमेरिका में 3,000 से अधिक नकली गिब्सन इलेक्ट्रिक गिटार जब्त

लॉस एंजिल्स (ईएमएस)। अमेरिका में सीमा शुल्क विभाग ने 3,000 से अधिक नकली गिब्सन इलेक्ट्रिक गिटार पकड़े हैं। यह रिकॉर्ड नकली म्यूजिकल सामानों की जब्ती है। इसकी जानकारी अमेरिका के सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा विभाग ने दी।

साल 1902 में कलामजू, मिशिगन में स्थापित प्रतिष्ठित अमेरिकी गिटार ब्रांड ने अपने सभी उपकरणों का उत्पादन विशेष रूप से अमेरिकी में किया है। एक नए प्रामाणिक गिब्सन गिटार की कीमत आमतौर पर 500 यूएस डॉलर से 2,000 डॉलर के बीच होती है। जबकि, कुछ मॉडल 10,000 डॉलर में भी बिकते हैं।

सीमा शुल्क अधिकारियों के अनुसार, यह नकली गिटार ई-कॉमर्स बाजार के लिए थे, अगर असली होते, तब उनकी अनुमानित कीमत 18 मिलियन डॉलर होती। इसतरह के प्रोडक्ट अक्सर निम्न-गुणवत्ता या खराब सामग्रियों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। यह हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। साथ ही इसका घटिया क्वालिटी का सामान आग लगने के खतरे को भी पैदा कर देते हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक यह जब्ती उपभोक्ताओं के लिए ऑनलाइन या संदिग्ध स्त्रोतों से धोखाधड़ी वाले उत्पादों को खरीदने के जोखिमों के लिए जागरुक करने वाली थी। पोर्ट के निदेशक अफ्रीका बेल ने कहा, वह लोग धोखेबाज हैं और यह सब अमेरिकी उपभोक्ता को धोखा देने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा है। बेल ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में, दक्षिणी कैलिफोर्निया बंदरगाह पर 2 बिलियन डॉलर से अधिक के नकली उत्पाद जब्त किए गए थे। पोर्ट द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, लॉस एंजिल्स का पोर्ट अमेरिका का सबसे व्यस्त कंटेनर पोर्ट है, जिसमें 2023 में 292 बिलियन डॉलर का माल गुजरा था।

बाइडेन का डबल गेम, यूक्रेन को परमाणु हथियार देने की बात कह कर, ट्रंप के लिए पैदा कर रहे संकट

वाशिंगटन (ईएमएस)। रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर कई आरोप लग रहे हैं, खासकर उन निर्णयों को लेकर जो उन्होंने संघर्ष में लिए हैं। बाइडेन प्रशासन, रूस के साथ युद्ध को बढ़ावा देने के आरोपों का सामना कर रहा है। सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब बाइडेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की मंजूरी दी, और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की परमाणु धमकियों के बाद भी यूक्रेन को सैन्य सहायता भेजने का सिलसिला जारी रखा। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बाइडेन प्रशासन, रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को परमाणु हथियार देने पर विचार कर रहा है, इससे तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ गई है।

इस मुद्दे पर अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य मार्जोरी टेलर ग्रीन ने बाइडेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मार्जारी के अनुसार, बाइडेन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता नहीं सौंपना चाहते हैं और इसके लिए वे न्यूक्लियर वॉर का जोखिम लेने को तैयार हैं। उन्होंने इस फैसले को देशद्रोह करार देकर कहा कि यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। ग्रीन का दावा है कि बाइडेन प्रशासन रूस-यूक्रेन के बीच परमाणु युद्ध शुरू करवा सकता है, ताकि सत्ता हस्तांतरण में अड़चन डाली जा सके।

रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कुछ अमेरिकी और यूरोपीय अधिकारियों ने यूक्रेन को वे परमाणु हथियार वापस करने का प्रस्ताव दिया है, जो यूक्रेन ने सोवियत संघ के विघटन के समय सौंपे थे। हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया था कि इस निर्णय पर अमल करना बेहद कठिन हो सकता है, और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि पुतिन, ट्रंप की मध्यस्थता में यूक्रेन के साथ सीजफायर डील पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इसके विपरीत, बाइडेन प्रशासन के निर्णयों से संघर्ष और बढ़ सकता है, जिससे यह भी संभावना है कि यदि परमाणु युद्ध हुआ, तब ट्रंप के लिए युद्ध को रोकना और सत्ता हस्तांतरण दोनों ही मुश्किल हो जाएंगे। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि उनकी प्राथमिकता युद्ध को जल्दी समाप्त करना है, जबकि बाइडेन के फैसले युद्ध को और बढ़ा सकते हैं, जिससे सत्ता हस्तांतरण में रुकावट आ सकती है।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच रूस ने बाइडेन प्रशासन की परमाणु योजना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि पश्चिमी देशों का यूक्रेन को परमाणु हथियार देने का विचार गैर-जिम्मेदाराना है और यह दर्शाता है कि वे वास्तविकता से पूरी तरह अनजान हैं। पेसकोव का कहना था कि यदि ऐसा हुआ, तब रूस को भी न्यूक्लियर हमले पर विचार करना पड़ सकता है।

शवों के साथ सोता था सीरियल किलर, 25 दिन में पांच को उतारा मौत के घाट

अहमदाबाद (ईएमएस)। वलसाड में एक सीरियल किलर ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। एक छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोप में गिरफ्तार राहुल जाट ने पुलिस को बताया कि उसने 25 दिनों में पांच लोगों की हत्यायें की हैं। वह हत्या के बाद कई बार तो शवों के साथ ही सो जाता था। वहीं पुलिस ने आपरोपी को पांच दिसंबर तक रिमांड पर लिया है। राहुल हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है और उसके खिलाफ राजस्थान व उत्तर प्रदेश में भी एक दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस मौके पर अधिकारी ने बताया कि छात्रा की हत्या से एक दिन पहले राहुल ने तेलंगाना के सिकंदराबाद में लूट के दौरान एक महिला की हत्या की थी। अक्टूबर में उसने महाराष्ट्र के सोलापुर रेलवे स्टेशन के पास एक महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी। इससे पहले बंगाल के हावड़ा स्टेशन पर एक बुजुर्ग को लूटने के बाद चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया था। इसके अलावा कर्नाटक के मुल्की स्टेशन पर एक मामूली विवाद पर एक यात्री को चाकू मारकर कत्ल किया था। वह अलग-अलग राज्यों में अपराध करके लगातार अपनी लोकेशन बदल लेता था। उसने चार राज्यों कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, और महाराष्ट्र में लूट और हत्या की वारदात की थी। पुलिस के अनुसार वह ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर अपराध करता था। वहीं इस मामले में वलसाड के एसपी करणराज वाघेला ने कहा कि यह गिरफ्तारी कई राज्यों की पुलिस और व्यापक खोज अभियान की वजह से संभव हो सकी है। पुलिस ने बताया कि वलसाड में रहने वाली बीकॉम की छात्रा 14 नवंबर को ट्यूशन से घर लौट रही थी। तभी सुनसान इलाके में राहुल ने उसे झाड़ियों में खींच लिया और दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या कर दी और वहां से चला गया। कुछ देर बाद साइको किलर लौटा और उसने शव के साथ भी दुष्कर्म किया। वहीं सीरियल किलर गिरफ्तारी में रेलवे ट्रैक के पास और पार्किंग एरिया के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अहम साबित हुई। जब उसकी तलाश शुरू की गई तो पता चला कि आरोपी पहले भी एक चोरी के मामले में पकड़ा जा चुका है और उसे सूरत की लाजपोर जेल में रखा गया था।

ऑवरटेक के प्रयास में ट्रक और बस के बीच हुई दुर्घटना में 3 लोगों की मौत

आणंद (ईएमएस)। मंज़िल पर जल्द पहुंचने का प्रयास जानलेवा साबित हो सकता है, इसके बावजूद चालक अपने वाहन की रफ्तार कम नहीं करते। कभी कभार खासकर हाईवे पर ऑवरटेक का प्रयास में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे ही एक घटना आणंद में तारापुर-धर्मज हाईवे से सामने आई है, जिसमें ऑवरटेक के प्रयास में लक्जरी बस और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि अन्य कई घायल हो गए, जिन्हें इलाज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक प्राइवेट ट्रावेल्स कंपनी की एक बस राजकोट से यात्रियों को लेकर सूरत की ओर जा रही थी। बस जब आणंद जिले में तारापुर-धर्मज हाईवे से गुजर रही थी तब वडदला गांव पाटिया के निकट ऑवरटेक के प्रयास में ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतना जबर्दस्त थी कि बस में सवार तीन यात्रियों की मौत हो गई। बस में सवार राजकोट के 32 वर्षीय ध्रुव रूडाणी, 67 वर्षीय मनसुखभाई कोराट और 39 वर्षीय कल्पेश जियाणी की इस हादसे में मौत हो गई जबकि अन्य कई घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की खबर मिलते ही आणंद जिले की पेटलाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्यवाही शुरू की है।

पिता को ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर बेटे से ऐंठे 1.15 करोड़ रुपए

सूरत (ईएमएस)। शहर के पार्ले पॉइंट क्षेत्र में रहनेवाले एक व्यवसायी को उसके पिता को ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर रु. 1.15 करोड़ से अधिक रकम ऐंठ ली गई। व्यवसायी की शिकायत मिलने पर सूरत साइबर क्राइम ने मामले की जांच शुरू की है। जानकारी के मुताबिक सूरत के पार्ले पॉइंट क्षेत्र के देवर्षि बंगलोज में रहनेवाले 59 वर्षीय मेहुल गोवर्धनभाई रेशमवाला शहर के सब जेल के सामने पूजा एजेंसी के नाम से इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बेचते हैं। गत 12 अक्टूबर को मेहुल के पिता गोवर्धनभाई रेशमवाला को अज्ञात नंबर से फोन आया। कॉल करने वाले अपनी पहचान डीएचएल कूरियर के कर्मचारी राहुल कुमार के तौर पर दी। फोन पर राहुल ने बताया कि गत 6 अक्टूबर को मुंबई से चीन के बीजिंग भेजे गए पार्सल की डिलीवरी नहीं हुई है। पार्सल के लेपटोप, पासपोर्ट, बैंक डॉक्युमेंट समेत 400 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुआ है। फोन पर इतनी बात बताने के बाद राहुल ने मुंबई पुलिस के राजेश प्रधान को फोन दे दिया। राजेश प्रधान ड्रग्स को लेकर गोवर्धनभाई रेशमवाला को झाड़ने लगे। इतना ही नहीं राजेश प्रधान नामक शख्स ने गोवर्धनभाई के खिलाफ अभद्र भाषा का भी उपयोग किया। जिससे गोवर्धनभाई डर गए और कहा कि वह वृद्ध होने के साथ ही बीमार भी हैं। रात के दो बजे हैं और इस समय मुझे बेवजह परेशान न करें। इस पर सामने से कहा गया कि अगर इसका किसी से जिक्र किया तो पूरे परिवार को जेल जाना पड़ेगा और तुम्हें गोली मार दी जाएगी। जिसके बाद दूसरे दिन सुबह प्रकाश अग्रवाल नामक शख्स ने वीडियो कॉल किया और खुद को सीबीआई निदेशक और राहुल नवीन ईडी अधिकारी होने बताते हुए कहा कि अगर पूरे मामले से बचना है तो हम कहें ऐसा करना होगा। उस वक्त भी कथित अधिकारी बनकर बात कर रहे शख्सों ने गोवर्धनभाई का डराया-धमकाया और अभद्रता भी की। कथित अधिकारियों ने गोवर्धनभाई से कहा कि आपके बैंक खाते में 2 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है और उसमें आपने दो लाख रुपए बतौर कमीशन लिए हैं। इस मामले में आप के केजरीवाल, एमपी, एमएलए और पीएम मोदी भी संलिप्त हो सकते हैं। पूरा मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है, इसलिए आपको इस संदर्भ में किसी के साथ कोई चर्चा नहीं करनी। अगर किसी से इस बारे में चर्चा की तो आपकी और पूरे परिवार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जिसके बाद बतौर सीबीआई निदेशक परिचय देनेवाले प्रकाश अग्रवाल ने कहा कि अगर पूरे मामले से बचना है तो आपके पास जितनी संपत्ति और गुप्त जानकारी है वह हमारे साथ साझा करनी होगी। धमकी से भयभीत गोवर्धनभाई ने शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश का पूरा ब्यौरा वीडियो कॉल के जरिए साझा कर दिया। घटना के बाद 16 अक्टूबर को गोवर्धनभाई ने शेयर बाजार और म्यूच्युअल फंड से अपनी रकम निकाल ली, जो उनके एचडीएफसी बैंक में जमा हुई थी। जिसके बाद फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर कथित अधिकारियों ने 23 अक्टूबर को नोटिस भेजी और बचने के लिए सिक्युरिटी डिपोजिट के तौर पर रकम ट्रांसफर करने को कहा। धमकी से डरे गोवर्धनभाई ने पहले रु. 75 लाख और बाद में रु. 40.50 लाख अपने एकाउंट से आरटीजीएस के जरिए जमा करवा दिए। इस प्रकार साइबर ठगों ने गोवर्धनभाई से रु. 1.15 करोड़ रुपए अधिक ऐंठ लिए।

बीजेड ग्रुप के 6000 करोड़ के घोटाले पर भाजपा सरकार की चुप्पी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

अहमदाबाद (ईएमएस)। बीजेड सॉल्यूशन के भूपेन्द्रसिंह झाला के 6,000 करोड़ रुपये के विकास घोटाले पर भाजपा सरकार से जवाब मांगते हुए गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया संयोजक एवं प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा कि साबरकांठा में ग्रोमोर एजुकेशन कैंपस की भागीदारी से बीजेड ग्लोबल एजुकेशन कैंपस के उद्घाटन में भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व में भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल, प्रदेश महासचिव रजनीभाई पटेल, शिक्षा मंत्री श्री कुबेरभाई डिंडोर, खाद्य नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री श्री भीखूसिंह परमार और वरिष्ठ भाजपा नेता उपस्थित थे। इस शिक्षा परिसर में बीजेड सॉल्यूशन की भागीदारी थी। ऐसा लगता है जैसे भाजपा का चोला पहनने के बाद भ्रष्टाचार और लूट का लाइसेंस मिल जाता है। छोटे परिवारों ने लालच में आकर बीजेड ग्रुप पैसा निवेश किया। पोंजी स्कीम के नाम पर ऐसे कई लोग राज्य भर में काम कर रहे हैं। फिर भी गृह मंत्री ने ख्याति और बीजेड पर एक भी शब्द नहीं बोला। कॉल विवरण और उन सभी के खिलाफ जांच करें जिनके भूपेन्द्रसिंह झाला से संबंध हैं। भूपेन्द्र सिंह झाला की तारीफ करने वालों की भी जांच होनी चाहिए। यह भाजपा नेता ही थे जिन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वे एक को दोगुना और चार गुना करने में विशेषज्ञ हैं। अगर भूपेन्द्रसिंह झाला जैसे लोग बहुत होशियार हैं तो सरकार को ऐसे लोगों की वित्तीय सलाह और सेवा लेनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि अनेक घोटालों और घोटालों में घिरी भाजपा राज में एक भी घोटाले में अनुकरणीय कार्रवाई की जाए, ताकि लूट का धंधा बंद हो। राजनीतिक संरक्षण देने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि बीजेड सॉल्यूशन के मास्टरमाइंड भूपेन्द्रसिंह झाला भाजपा सदस्य हैं और उन्हें कई भाजपा नेताओं के करीबी के रूप में देखा जाता है। यह एक बड़ी धोखाधड़ी है जिसमें आम-मध्यम वर्ग के हजारों छोटे निवेशक शामिल हैं और शुरुआती रिपोर्ट में 14,000 से अधिक निवेशकों के शिकार होने की बात सामने आई है। भारतीय रिजर्व बैंक, गुजरात सरकार ब्याज संबंधी कानून की खामियों का फायदा उठाकर लूट का कारोबार चलाया जा रहा है। समझौते के आधार पर बड़े पैमाने पर हुए फर्जीवाड़े के बावजूद भाजपा सरकार के मंत्रियों और संत्रियों ने आंखें क्यों मूंद लीं? करोड़ों रुपये के वित्तीय लेनदेन में कई भाजपा नेताओं के आशीर्वाद से 6,000 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया। 2020 से 2024 तक केवल पांच वर्षों में 10,000 से अधिक धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज की गई हैं। सामान्य-मध्यमवर्गीय परिवारों को बड़ी मुआवजा योजना के नाम पर 6000 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने वाले बीजेड सॉल्यूशन के भूपेन्द्रसिंह झाला ने ग्रोमोर इंस्टीटयूशन नामक शैक्षणिक कॉम्प्लेक्स के साथ साझेदारी की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सी.आर. पाटिल, 18 जनवरी 2024 को शिक्षा मंत्री, पूर्व गृह मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री, भाजपा के शीर्ष पदाधिकारियों-विधायकों की मौजूदगी में होने वाले उद्घाटन कार्यक्रमों पर भाजपा सरकार चुप क्यों है? बीजेड समाधान के नाम पर, स्थानीय प्रणाली की निगरानी के बिना खुले व्यापारिक कार्यालय खोलना कैसे संभव है? गुजरात के कई जिलों-शहरों और छोटे कस्बों में पोंजी स्कीम के नाम पर चल रहे लूट के धंधे से सख्ती से निपटा जाना चाहिए ताकि गरीब-आम-मध्यम वर्गीय परिवार इसका शिकार न बनें।

चचेरे भाई ने बहन को बनाया हवस का शिकार, ब्लैकमेल कर रुपये भी मांगता था

सूरत (ईएमएस)। ऐसी कई खबरें सामने आ चुकी हैं कि बेटियां परिवार में भी अब सुरक्षित नहीं हैं। फिलहाल सूरत से ऐसी ही एक घटना सामने आई है। सूरत में चचेरे भाई ने ब्लैकमेल कर बहन को हवस की शिकार बनाया। इतना ही नहीं वह पीड़िता से रुपयों की मांग करता था। इस मामले में लड़की के परिवार ने राजस्थान में शिकायत दर्ज कराई थी। राजस्थान पुलिस ने शिकायत दर्ज कर इसे लिंबायत पुलिस को स्थानांतरित कर दिया। जानकारी के मुताबिक सूरत में रहनेवाले जिशान मेहबूब ने अपनी चचेरी बहन को होटल में अपनी हवस का शिकार बनाया। इतना ही नहीं जिशान ने घटना की तस्वीरें भी खींच लीं और उसके जरिए वह चचेरी बहन को ब्लैकमेल करने लगा। पीड़िता का अन्य युवक से रिश्ता हो गया था, इसके बावजूद जिशान ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जिशान ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने किसी से शादी की तो वह तस्वीरें वायरल कर देगा। जानकारी के मुताबिक 10 नवंबर को जब पीड़ित युवती की शादी थी तब उसके मंगेतर को जिशान ने निजी पलों की तस्वीरें भेज दीं। जिससे बारात बगैर शादी लौट गई। जिशान मेहबूब अक्सर पीड़ित युवती से रुपए मांगता रहता था। जिशान की हरकतों से तंग आकर आखिरकार पीड़िता के परिवार ने राजस्थान में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। राजस्थान पुलिस ने पूरा सूरत की लिंबायत पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है और उसके आधार पर मामले की जांच की जा रही है।

दादरा नगर हवेली में कार पलटने से सूरत के चार दोस्तों की मौत

सूरत (ईएमएस)। दादरा नगर हवेली के दूधनी के निकट कार पलटने से उसमें सवार सूरत के चार दोस्तों की मौत हो गई। जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना उस समय हुई जब कार में सवार सूरत को लोग खानवेल की ओर आ रहे थे। जानकारी के मुताबिक सूरत में रहनेवाले 45 वर्षीय हसमुख मांगूकिया, 45 वर्षीय सुजीत पुरुषोत्तम कलाडिया, 38 वर्षीय संजय चंदू गज्जर, 34 वर्षीय हरेश वडोहडिया और 24 वर्षीय सुनील कालीसास निकुडे दादरा नगर हवेली गए थे। दादरा नगर हवेली में सूरत के पांचों लोग कार में खानवेल-दूधनी रोड पर उपला मेढा गांव के निकट से गुजर रहे थे। उस वक्त कार चालक ने स्टेयरिंग से नियंत्रण गंवा दिया और कार अनियंत्रित होकर तीन-चार पलटी खा गई। इस हादसे में 24 वर्षीय सुनील कालीदास निकुडे की जान बाल बाल बच गई। जबकि कार में सवार अन्य चार दोस्तों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए और कार में फंसे लोगों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला

आईपीएस नीरजा गोटरू गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड की चेयरमैन नियुक्त

गांधीनगर (ईएमएस)। गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड को लेकर अहम खबर सामने आई है। आईपीएस नीरजा गोटरू को पुलिस भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जीपीएससी की नियुक्ति के कारण आईपीएस हसमुख पटेल के इस्तीफे के बाद यह पद रिक्त हो गया था। बता दें कि आईपीएस हसमुख पटेल को गुजरात लोक सेवा आयोग (जीपीएससी) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। जीपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हसमुख पटेल ने पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। अब पुलिस भर्ती बोर्ड के रिक्त अध्यक्ष पद पर आईपीएस आईपीएस नीरजा गोटरू का चयन हो गया है। नीरजा गोटरू 1993 बैच की आईपीएस हैं। इससे पहले उन्हें गांधीनगर में अतिरिक्त डीजीपी प्रशिक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। आईपीएस अधिकारी नीरजा गोटरू अहमदाबाद यातायात विभाग में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में भी काम कर चुकी हैं।

फिजी डेयरी उद्योग, एआई, आईसीटी तथा साइबर सिक्योरिटी क्षेत्रों में गुजरात के सहयोग के लिए तत्पर

- गांधीनगर में फिजी के उप प्रधानमंत्री मनोआ कामिकामिका ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार भेंट की

गांधीनगर (ईएमएस)। फिजी के उप प्रधानमंत्री मनोआ कामिकामिका ने गुरुवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार भेंट की। भूपेन्द्र पटेल के साथ इस शिष्टाचार भेंट तथा बैठक में बातचीत के दौरान फिजी के उप प्रधानमंत्री ने गुजरात द्वारा डेयरी उद्योग सहित कृषि क्षेत्र में जो वैश्विक ख्याति प्राप्त की गई है, उसकी विशेषज्ञता का लाभ फिजी को भी प्राप्त हो; इसके लिए परस्पर सहयोग की तत्परता व्यक्त की। कामिकामिका ने डेयरी उद्योग के अलावा एआई, आईसीटी तथा साइबर सिक्योरिटी सेक्टर में भी गुजरात द्वारा फिजी का सहयोग किए जा सकने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया।

फिजी के उप प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर गुजरात को विकास का रोल मॉडल एवं ग्रोथ इंजन बनाए जाने के विषय में भी विस्तार से चर्चाएँ कीं। कामिकामिका ने नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार पदभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहले फिजी की यात्रा किए जाने के संस्मरण भी ताजा किए।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के रिन्यूएबल एनर्जी एवं ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में लीड लिए जाने की पृष्ठभूमि देते हुए बताया कि कच्छ में विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क निर्माणाधीन है। इतना ही नहीं, गुजरात में एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बायोमास, बायोगैस तथा बायोफ्यूल को प्रोत्साहन देने वाली वेस्ट टु एनर्जी पॉलिसी है।

फिजी के उप प्रधानमंत्री ने कहा कि फिजी में गन्ने का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। इस संदर्भ में इथेनॉल प्रोडक्शन में फिजी गुजरात का सहयोग कर सकता है।

भूपेंद्र पटेल ने यह कहते हुए कि फिजी के उप प्रधानमंत्री को आमंत्रण दिया कि गुजरात द्वारा पॉलिसी ड्रिवन स्टेट के रूप में विभिन्न उद्योगों एवं उभरते क्षेत्रों के लिए बनाई गई नीतियों तथा बहुविध सेक्टर्स में गुजरात की उपलब्धियों के अध्ययन व निरीक्षण के लिए फिजी का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल गुजरात आए। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात फिजी को जिस सेक्टर में सहभागिता व मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, उसमें अपना सहयोग देगा। उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की कि उच्च स्तरीय प्रतिनिधमंडल की इस गुजरात यात्रा से भारत-फिजी के बीच प्रभावशाली एवं परिणामदायी सहभागिता का सुदृढ़ संबंध स्थापित होगा।

उन्होंने जोड़ा कि गुजरात ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन 'विकसित भारत@2047' में विकसित गुजरात के जरिये अग्रसर रहने का संकल्प किया है। इस उद्देश्य से 'विकसित गुजरात@2047' का रोड मैप तैयार किया गया है तथा अर्निंग वेल-लिविंग वेल के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी प्रायोरिटी दी गई है। मुख्यमंत्री ने फिजी के उप प्रधानमंत्री मनोआ कामिकामिका को यह भी बताया कि गिफ्ट सिटी अंतरराष्ट्रीय फाइनैंशियल हब के रूप में उभर रही है।

फिजी के उप प्रधानमंत्री कामिकामिका मुख्यमंत्री के साथ इस शिष्टाचार भेंट के बाद गिफ्ट सिटी तथा आणंद स्थित अमूल के दौरे पर भी जाने वाले हैं। फिजी के उप प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री के बीच इस हुई बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एम. के. दास, उद्योग विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती ममता वर्मा तथा मुख्यमंत्री की सचिव श्रीमती अवंतिका सिंह भी उपस्थित रहे।

दो दिन बाद गुजरात में बढ़ेगी ठंड, 11 से 14 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की संभावना

अहमदाबाद (ईएमएस)। मौसम विभाग से गुजरात में ठंड को लेकर अहम खबर सामने आई है। मौसम विभाग की मानें तो दो दिन बाद गुजरात में ठंड का जोर बढ़ेगा और न्यूनतम तापमान 11 से 14 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। इस बीच राज्य के कई शहरों का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक पहुंच तक पहुंच गया है। अगले दो दिन तक राज्य में मौसम ऐसा रहेगा और उसके न्यूनतम तापमान गिरावट आएगी। हवा की दिशा बदलने से ठंड का जोर बढ़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार से राज्य के न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। हवा की दिशा बदलने और उत्तर भारत में बर्फबारी के कारण गुजरात में ठंड का जोर बढ़ेगा। फिलहाल गुजरात के कई शहरों का तापमान 15 से 18 डिग्री के बीच होने से ठंड अहसास नहीं हो रहा। लेकिन दो दिन बाद न्यूनतम तापमान गिरने से लोगों को ठंड महसूस होगी।

ख्याति हॉस्पिटल कांड : जीएमसी ने डॉ. प्रशांत वजीरानी का लाइसंस सस्पैंड किया

अहमदाबाद (ईएमएस)। गुजरात मेडिकल काउंसिल (जीएमसी) ने ख्याति हॉस्पिटल कांड में संलिप्त डॉ. प्रशांत वरीरानी के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। जीएमसी ने डॉ. प्रशांत वजीरानी का एमबीबीएस, एमएस, डीएनबी का लाइसेंस तीन साल के लिए सस्पैंड कर दिया है। बता दें कि ख्याति हॉस्पिटल कांड को लेकर जांच और कार्रवाई जारी है। ख्याति हॉस्पिटल कांड के आरोपी डॉ. प्रशांत वजीरानी आर्थिक लाभ के लिए मनमाने ढंग से ऑपरेशन कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक डॉ. प्रशांत वजीरानी को ख्याति हॉस्पिटल से 24 लाख रुपये लेने थे। बकाया रकम नहीं मिलने पर डॉ. प्रशांत ने ख्याति हॉस्पिटल में काम करना बंद कर दिया था। लेकिन 4 महीने बाद आरोपी डॉ. प्रशांत फिर से बकाया रकम वसूलने के लिए अस्पताल में शामिल हो गया था। अस्पताल में दोबारा शामिल होने के बाद डॉ. प्रशांत ने लगभग 20 सर्जरी कीं। अहमदाबाद के बहुचर्चित ख्याति अस्पताल कांड में एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। आयुष्मान योजना के तहत सरकारी पैसा वसूलने के लिए मरीजों को डरा-धमका कर ऑपरेशन किये गये। डॉक्टर मरीज़ों को डरावनी रिपोर्ट दिखाते थे कि नली में ब्लॉक है और दिल का दौरा पड़ेगा। वे मरीजों के बीच यह कहकर डर का माहौल पैदा करते थे कि हार्ट अटैक होने पर 3 से 4 लाख रुपये का खर्च आएगा। ख्याति अस्पताल में जांच करने वाले मरीजों को स्टेंट भी लगाती थीं। अधिकांश मरीजों को पता ही नहीं था कि उन्हें स्टेंट लगाया गया है। पीएमजेएवाई योजना से पैसे ऐंठने के लालच में गांवों में डेरा डालकर मरीजों को ख्याति अस्पताल बुलाया जाता। जहां डॉक्टर प्रशांत वजीरानी अस्पताल में आने वाले मरीजों का गलत ऑपरेशन करता था। जिसमें कई मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इस मामले की जांच फिलहाल अहमदाबाद क्राइम ब्रांच कर रही है। ख्याति हॉस्पिटल के ट्रस्टी, मैनेजर और डॉक्टर समेत 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने साजिश रचकर सरकारी योजना का गलत फायदा उठाया है। जिसमें ख्याति हॉस्पिटल के चेयरमैन कार्तिक पटेल, सर्जन डॉ. संजय पटोलिया, डायरेक्टर चिराग राजपूत, कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. प्रशांत वजीरानी समेत राजश्री प्रदीप कोठारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। इस मामले में अब तक प्रशांत वजीरानी समेत कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच डॉ. प्रशांत वजीरानी का लाइसेंस गुजरात मेडिकल काउंसिल ने तीन साल के लिए रद्द कर दिया है। ख्याति कांड के बाद गुजरात मेडिकल काउंसिल ने सबसे बड़ी कार्रवाई की है। डॉ. प्रशांत वजीरानी का एमबीबीएस, एमएस, डीएनबी का लाइसेंस तीन साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। यानी प्रशांत वजीरानी अब खुद प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे।

वलसाड-भगत की कोठी तथा बांद्रा टर्मिनस-बाड़मेर एक्सप्रेस अब सुपरफास्ट ट्रेन बनेगी

अहमदाबाद (ईएमएस)। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वलसाड-भगत की कोठी तथा बांद्रा टर्मिनस-बाड़मेर एक्सप्रेस को सुपरफास्ट ट्रेनों में परिवर्तित किया जाएगा। अब इन ट्रेनों को नए नंबर दिए जाएंगे। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों में होने वाले परिवर्तनों का विवरण इस प्रकार है:

□ ट्रेन संख्या 19009/19010 बांद्रा टर्मिनस- बाड़मेर हमसफर एक्सप्रेस (साप्ताहिक) की ट्रेन संख्या में परिवर्तन

ट्रेन संख्या 19009 बांद्रा टर्मिनस- बाड़मेर हमसफर एक्सप्रेस को 03 जनवरी, 2025 से नया नंबर 21901 दिया जाएगा। इसी तरह ट्रेन संख्या 19010 बाड़मेर- बांद्रा टर्मिनस हमसफर एक्सप्रेस को 04 जनवरी, 2025 से नया नंबर 21902 दिया जाएगा।

□ ट्रेन संख्या 19055/19056 वलसाड- भगत की कोठी एक्सप्रेस (साप्ताहिक) की ट्रेन संख्या में परिवर्तन

ट्रेन संख्या 19055 वलसाड- भगत की कोठी एक्सप्रेस को 07 जनवरी, 2025 से नया नंबर 22991 दिया जाएगा। इसी तरह ट्रेन संख्या 19056 भगत की कोठी-वलसाड एक्सप्रेस को 08 जनवरी, 2025 से नया नंबर 22992 दिया जाएगा। ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

भारतीय रेलवे का यात्रियों के हित में एक और कदम, लॉंच किया "संरक्षा मोबाइल एप्लिकेशन"

अहमदाबाद (ईएमएस)। भारतीय रेलवे ने आज पूरे देश में संरक्षा मोबाइल एप्लीकेशन लांच करके यात्री संरक्षा की दिशा में एक और कदम उठाया। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य भारतीय रेलवे के फ्रंटलाइन संरक्षा श्रेणी के कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के माध्यम से रेल संरक्षा में सुधार करना है। रेलवे बोर्ड के सदस्य परिचालन और व्यवसाय विकास रविंदर गोयल ने आज सभी मंडल रेल प्रबंधक, प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक ,प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक और भारतीय रेल के सभी मंडलों के अधिकारियों की उपस्थिति में संरक्षा मोबाइल एप्लीकेशन लांच किया। इस एप्लीकेशन को 2013 बैच के आईआरटीएस अधिकारी दिलीप सिंह ने डिजाइन किया है, जो वर्तमान में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। इस अवसर पर नागपुर मंडल की डीआरएम श्रीमती नमिता त्रिपाठी ने नागपुर मंडल में पायलट प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के बारे में बात की और बताया कि यह किस तरह से मंडल में सुरक्षा बढ़ाने में उपयोगी साबित हुआ है। अब रेलवे ने सभी जोनल रेलवे में इस एप को लांच करने का निर्णय लिया है, जिसमें 16 मंडलों को शुरू में रोलआउट के लिए चुना गया है। यह एप्लीकेशन भारतीय रेलवे के विषय संबंधी ज्ञान को सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा एनालिटिक्स और भविष्य में आर्टीफीशियल इंटेलिजेंस के संभावित लाभ के साथ एकीकृत करता है, ताकि रेलवे कर्मचारियों की प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक बुद्धिमान, प्रभावी और स्केलेबल प्रणाली प्रदान की जा सके। इसमें स्मार्ट लर्निंग और फीडबैक मैकेनिज्म की सुविधा है जो बहु-स्तरीय, वास्तविक समय फीडबैक और निगरानी को संभव बनाता है।

डीएसपी म्यूचुअल फ़ंड ने डीएसपी बिज़नेस साइकिल फ़ंड किया लॉन्च

मुंबई, 26 नवंबर, 2024: डीएसपी म्यूचुअल फ़ंड ने डीएसपी बिज़नेस साइकिल फ़ंड लॉन्च करने की घोषणा की है, जो बिज़नेस साइकिल के आधार पर निवेश थीम के बाद एक ओपन-एंडेड इक्विटी है।

यह फ़ंड निवेशकों को लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनियों सहित कई बाज़ार पूँजीकरण में निवेश करने का अवसर देता है। निवेश की योजना उन उद्योगों और क्षेत्रों के लिए ऐसेट को गतिशील रूप से आवंटित करने पर केंद्रित है जो शक्तिशाली विकास क्षमता दिखाते हैं, बुनियादी बातों में सुधार करते हैं और आकर्षक मूल्यांकन करते हैं।

ठथीम का समय पर प्रवेश और निकास अपने आप में निवेशकों के लिए मुश्किल हो सकता है और कभी-कभी गड़बड़ियों का कारण बन सकता है। किसी क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद पूँजी को फिर से इस्तेमाल करने के लिए भी गहन मूल्यांकन की ज़रूरत होती है। डीएसपी बिज़नेस साइकिल फ़ंड को योजना के अनुसार जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करते हुए बिज़नेस साइकिल के अलग-अलग चरणों के ज़रिए नैविगेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। डीएसपी म्यूचुअल फ़ंड के फ़ंड मैनेजर चरणजीत सिंह ने कहा, ठहमारा मानना है कि यह फ़ंड निवेशकों को बदलते बाज़ार की गतिशीलता को लाभकारी बनाने का एक अनोखा अवसर देगा।''

इनऑर्बिट मॉल की ब्लैक फ्राइडे सेल: अविश्वसनीय डील्स की प्रतीक्षा!

वडोदरा: इनऑर्बिट मॉल 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक अपनी बहुप्रतीक्षित ब्लैक फ्राइडे सेल के साथ खरीदारों के लिए एक अविश्वसनीय खरीदारी अनुभव लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह तीन दिवसीय सेल विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय ब्रांडों पर भारी छूट प्रदान करती है, जिससे यह फैशन, सौंदर्य, घरेलू सामान और बहुत कुछ खरीदने का सही समय है।

शॉपर्स स्टॉप, मार्क्स एंड स्पेंसर, पैंटालून, मैक्स, गैस, नायका, ज़िवामे और रंगरीति जैसे ब्रांडों पर 50% तक की छूट जैसे आकर्षक ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, जबकि स्वारोवस्की पर 30% तक की छूट होगी। जैक एंड जोन्स, ओनली और आर्के पर भी अद्भुत सौदे पा सकते हैं, जबकि जिंक लंदन चयनित शैलियों पर 30% की छूट दे रहा है। साउच अपने संपूर्ण माल पर 25% की छूट दे रहा है, जबकि औम्क्ति चुनिंदा माल पर 50% की छूट दे रहा है। प्यूमा, ट्रेंड्स

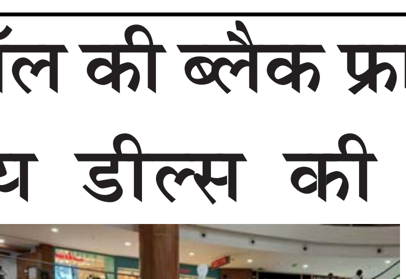

स्टीव मैडेन जैसे अन्य लोकप्रिय ब्रांड 50% तक की छूट दे रहे हैं, जबकि एल्डो और पियोरा फ्लैट 50% की छूट दे रहे हैं।

जो लोग खुद को खुश रखना चाहते हैं, उनके लिए एनरिच चुनिंदा सेवाओं पर 50ङ तक की छूट प्रदान करता है। आप रितु कुमार द्वारा बाथ एंड बॉडी वर्क्स, सुपरड्राई, बीबा फुटवियर, मैंगो, दा मिलानो और टाइमज़ोन पर विशेष छूट न चूकें।

इनऑर्बिट मॉल में यह ब्लैक फ्राइडे सेल सर्वोत्तम सौदों और छूट के लिए आदर्श खरीदारी स्थल है। अपने कैलेंडर चिह्नित करें और अविश्वसनीय कीमतों पर अपने पसंदीदा आइटम लेने के लिए तैयार हो जाएं!

पश्चिम रेलवे - वडोदरा मंडल

केन्द्रीयकृत यातायात नियंत्रण प्रणाली भवन का प्रावधान

ई-निविदा सूचना सं : DRM-BRC 105 वर्ष 2024-25 भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल रेल प्रबंधक (डब्ल्यूए/सी) पश्चिम रेलवे, वडोदरा द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए ई. निविदाएं आमंत्रित की जाती है। **(1) निविदा सं : DRM BRC 105 वर्ष** 2024-25 **(2) कार्य का नाम :** प्रतापनगर में केन्द्रीयकृत यातायात नियंत्रण प्रणाली भवन का प्रावधान। (पुनः आमंत्रित) (आर-1) **(3) कार्य की अनुमानित लागत (रु. में) :** ₹4,54,21,684.17 **(4) जमा की जाने वाली बोली सुरक्षा (रु. में) :** ₹3,77,100.00 **(5) निविदा प्रस्तुत करने और निविदा खोलने की तिथि और समय :** निविदा 16.12.2024 को 15.00 बजे से पहले प्रस्तुत की जानी है, और उसी तारीख को 15.30 बजे खोली जानी है। **(6) वेब साइड विवरण और सूचना का स्थान जहां पूर्ण विवरण देखा जा सकता है और कार्यालय का पता जहां से निविदा फार्म खरीदा जा सकता है :** मंडल रेल प्रबंधक (डब्ल्यूए/सी) पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा-4 वेब साइट @ www.ireps.gov.in 232

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

मालिक, मुद्रक-प्रकाशक व सम्पादक : लक्ष्मीचन्द जी. अग्रवाल द्वारा ब्रिजाशा ऑफसेट, सरसपुर, अहमदाबाद में मुद्रित करवाकर, स्वेतप्रित बिल्डिंग, खासवाड़ी, बहुचराजी रोड, वडोदरा से प्रकाशित किया। प्रातःकालीन E-mail: janhitaishi@yahoo.co.in Mob.9375504122 R.N.I. 64278/96